■ आषाढ़ शुक्ल - 8 ■ संवत 2082 ■ वर्ष - 20 ■ अंक - 334 ■ पृष्ठ - 8 ■ रु. 5/- बेंगलूरु » गुरुवार » 03-07-2025 ■ www.dakshinbharat.com ■ Email : news@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

आध्यात्मिक यात्रा की ओर प्रस्थान करें

जहां पावन हिमालय की गोद में है दिव्य स्नेह की अनुभूति

श्री अमरनाथ जी यात्रा -2025

- आध्यात्मिक महत्व
- दिव्य दर्शन
- अलौकिक दृश्य
- रोमांचक अनुभव
- मनमोहक ट्रैकिंग मार्ग
- सांस्कृतिक समावेश

एसएएसबी वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जम्मू व कश्मीर सरकार

@informationprjk Information & PR, J&K @diprjk @dipr_jk

बाबसाहेब अंबेडकर का अपमान छोटी भूल नहीं: सिंह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद द्वारा बाबासाहेब अंबेडकर का 'अपमान' किया जाना 'कोई छोटी गलती' नहीं है और यह 'दलितों के प्रति अनादर की मानसिकता' को दर्शाता है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष ने यह टिप्पणी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में की। यह बैठक बिहार में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आयोजित की जा रही है। सिंह ने कहा, ''लालू प्रसाद ने अपने पैरों के पास बाबासाहेब अंबेडकर की तस्वीर रखवाई थी। यह कोई छोटी गलती नहीं थी, बल्कि (यह) दलितों के प्रति अनादर की मानसिकता को दर्शाती है... बिहार को उन लोगों ने धोखा दिया है, जो समाजवाद की आड़ में अपने सामंती रवैये को छिपाते रहे हैं।''

पूर्व मुख्यमंत्री प्रसाद उस वीडियो क्लिप को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं, जिसमें अंबेडकर की तस्वीर उनके पैरों के पास देखी गई थी। यह उस दिन की घटना है जब लोग राजद प्रमुख को 78वें जन्मदिन पर बधाई देने उनके आवास पर आए थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले

महीने सीवान जिले में एक रैली में राजद सुप्रीमो पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्हें ''बिहार और देश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे''। हालांकि राजद ने स्पष्टीकरण दिया था कि तस्वीर एक समर्थक के हाथ में थी और भ्रम की स्थिति के लिए 'कैमरे के कोण' को जिम्मेदार ठहराया था। रक्षा मंत्री ने दावा किया, ''मैं इसे मुद्दा नहीं बना रहा हूं, (बल्कि) इसका उल्लेख वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर ने अपनी पुस्तक 'ब्रदर्स बिहारी' में विस्तार से किया है।'' केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''जब लालू प्रसाद सत्ता में थे, तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की याद में कुछ भी करने की जहमत नहीं उठाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के इस महान सपूत को भारत रत्न से सम्मानित किया।''

भाजपा नेता ने कहा, ''हम अतीत के बारे में बात करते रहते हैं ताकि युवा पीढ़ी राजद-कांग्रेस गठबंधन की बकवास बातों में न फंस जाए। उन्हें (युवाओं को) यह बताने की जरूरत है कि कैसे लालटेन (राजद का चुनाव चिह्न) ने अंधेरे को दूर करने के बजाय घरों में आग लगा दी।'' उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले कुछ दशकों में जब भी राज्य में जद (यू) अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार रही, तब बिहार ने ''अभूतपूर्व सफलता'' हासिल की है।

सिंह ने कहा, ''इस अवधि में न केवल आर्थिक विकास हुआ, बल्कि बिहार ने अपना खोया हुआ गौरव भी हासिल करना शुरू कर दिया। अंतरराष्ट्रीय पत्रिका 'द इकोनॉमिस्ट' ने कभी बिहार को भारत का अभिशाप कहा था, लेकिन बाद में इसकी (राज्य की) बदलाव की कहानी पर ध्यान देना पड़ा।''

अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे बड़ा 'कार्बन सिंक' : खांडू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

ईटानगर/भाषा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बुधवार को दावा किया कि उनके राज्य को भारत का सबसे बड़ा 'कार्बन सिंक' होने का गौरव हासिल है। 'कार्बन सिंक' का अभिप्राय ऐसी चीज से है जो वायुमंडल से जितना कार्बन छोड़ती है उससे कहीं ज्यादा अवशोषित करती है।

खांडू ने कहा कि अरुणाचल एक पारिस्थितिक महाशक्ति है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और देश को शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। खांडू ने अपने प्रशासन के 'पेमा 3.0-सुधार और विकास का वर्ष' अभियान के तहत एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात पर प्रकाश डाला कि अरुणाचल प्रदेश भारत के कुल कार्बन अवशोषण में उल्लेखनीय 14.38 फीसदी का योगदान देता है। उन्होंने दावा किया कि 79 फीसदी वन क्षेत्र के साथ राज्य में मौजूदा समय में 102.1 करोड़ टन 'कार्बन स्टॉक' है, जो देश में सबसे अधिक है।

'कार्बन स्टॉक' से तात्पर्य किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में किसी निश्चित समय पर संग्रहित कार्बन की कुल मात्रा से है। खांडू ने राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों में अरुणाचल के व्यापक योगदान को रेखांकित करते हुए कहा, ''यह समृद्ध 'कार्बन स्टॉक' भारत के लिए 2070 तक अपने शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने के लिहाज से अहम है।'' हालांकि, अरुणाचल प्रदेश का विशाल हरित क्षेत्र इसे शीर्ष 'कार्बन सिंक' बनाता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पहले से ही दिखाई दे रहे हैं और हकीकत का रूप लेते जा रहे हैं जिसके कारण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। खांडू ने कहा, ''हिमालय की गोद में स्थित अरुणाचल प्रदेश 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।''

बर्खास्त 'पात्र' अध्यापकों ने पुन: परीक्षा के विरूद्ध निकाली रैली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में अपनी नौकरी गंवा चुके 2016 के पैनल के 'पात्र' स्कूली अध्यापकों के एक समूह ने बुधवार को न्याय, पारदर्शिता तथा पुन: परीक्षा से छूट की मांग करते हुए यहां एक रैली निकाली।

प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा कि यहां करुणामयी से साल्ट लेक स्थित पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा विभाग के मुख्यालय विकास भवन तक निकाली गयी यह रैली 'भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए राज्य प्रायोजित साजिश' के खिलाफ विभिन्न विरोध प्रदर्शनों में से एक है।

विकास भवन के पास प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वे पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) और राज्य सरकार की मिलीजुली 'गहरी और गंदी साजिश' के शिकार हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक वैध चयन प्रक्रिया के माध्यम से अपनी नौकरी हासिल की थी और जांच में वे किसी भी भ्रष्टाचार घोटाले में शामिल नहीं पाये गये। विकास भवन के पास भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किये गये थे।

एक प्रदर्शनकारी ने कहा, ''हम परीक्षा में बैठने से नहीं डरते। लेकिन जब हम दागी नहीं हैं, तो हम क्यों परीक्षा में बैठें?''

प्रदर्शनकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि मुद्दा फिर से योग्यता साबित करने का नहीं बल्कि उनकी गरिमा और अधिकारों को बहाल करने का है। आंदोलनकारी शिक्षकों ने पारदर्शिता के लिए अपनी ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं की 'प्रतिच्छाया प्रति' तत्काल जारी करने की अपनी मांग दोहराई। उन्होंने उन पात्र उम्मीदवारों की एक व्यापक सूची प्रकाशित करने की भी मांग की, जिनके नाम किसी भी सीबीआई रिपोर्ट या भ्रष्टाचार से संबंधित निष्कर्षों में नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि भ्रम को रोकने और वैध रूप से भर्ती हासिल करने वालों की गरिमा को बनाये रखने के लिए पात्र और अपात्र उम्मीदवारों की सूची अलग-अलग प्रकाशित की जाएं।

उन्होंने दावा किया कि एसएससी और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये 15,203 बेदाग शिक्षकों की सूची जारी की जाए ताकि उन्हें बिना पुनर्परीक्षा प्रक्रिया के अपनी नौकरी वापस मिले।

नौकरी में आरक्षण: मुख्यमंत्री ने कहा, नगालैंड सरकार नीति की समीक्षा के लिए समिति बनाएगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोहिमा/भाषा। नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार नौकरी में आरक्षण की मौजूदा नीति की समीक्षा के लिए एक आयोग के गठन की तैयार कर रही है। उन्होंने लोगों से इस मुद्दे को लेकर धैर्य रखने का आग्रह किया।

कोहिमा में एक औपचारिक समारोह से इतर पत्रकारों से बात करते हुए रियो ने कहा कि आयोग का कार्य बहुत विस्तृत है और इसका निष्कर्ष तत्काल नहीं आ सकता। उन्होंने जोर दिया प्रशासन, आरक्षण या परिसीमन के संबंध में कोई भी सुधार जनगणना के बाद ही किया जाना चाहिए। जनगणना के 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। रियो ने कहा, ''हम अस्थायी व्यवस्था नहीं करना चाहते हैं। पूरे राज्य को गहन समीक्षा की प्रक्रिया से गुजरना होगा।'' मुख्यमंत्री ने मौजूदा प्रणाली में कुछ खामियों को स्वीकार किया और उन्हें व्यापक एवं निर्णायक रूप से दूर करने के लिए कदम उठाए जाने का भरोसा दिलाया। कोहिमा में 5 जनजातियों की आरक्षण नीति संशोधन समिति (सीओआरआरपी) की नागरिक

समाज संगठनों (सीएसओ) और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को प्रस्तावित आयोग से बाहर रखने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए रियो ने कहा, ''सरकार इस पर विचार करेगी। हमें इंतजार करना होगा।'' अंगामी, एओ, लोथा, रेंगमा और सेमा जनजातियों के प्रतिनिधियों वाली सीओआरआरपी ने आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए आयोग बनाने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के बावजूद सरकार की कथित निष्क्रियता पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। घोषणा का स्वागत करते हुए समिति ने या तो मौजूदा आरक्षण नीति को खत्म करने या फिर अनारक्षित कोटा पांचों जनजातियों को आवंटित करने की अपनी दोनों प्रमुख मांगें दोहराईं। सीओआरआरपी ने एक बयान में सरकार के साथ तीन जून को हुई बैठक के बाद कोई प्रगति न होने की आलोचना की। उसने कहा, ''हमारी प्रमुख मांगों पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है, न ही कोई आधिकारिक संचार प्राप्त हुआ है।''

उप्र एसटीएफ ने अंतरराज्यीय ऑक्सीटोसिन गिरोह का भंडाफोड़ किया

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की अवैध तस्करी और आपूर्ति में कथित रूप से शामिल एक अंतरराज्यीय गिरोह के तीन संदिग्ध सदस्यों को बुधवार को गिरफ्तार किया। एसटीएफ के अनुसार इस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का कथित तौर पर इस्तेमाल दुधारू मवेशियों और सब्जियों में किया जाता था।

एसटीएफ ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए लखनऊ के काकोरी थानाक्षेत्र में बुद्धेश्वर क्रॉसिंग के पास मोहन रोड पर एक मकान पर छापेमारी के दौरान लगभग 5,87,880 मिलीलीटर ऑक्सीटोसिन जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 1.20 करोड़ रुपए है। एसटीएफ ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान लखनऊ निवासी अनमोल पाल, अवधेश पाल और पास के सीतापुर जिले के खगेश्वर के रूप में हुई है। बरामद सामग्री में ऑक्सीटोसिन का स्टॉक, 12,000 रु. नकद, 800 खाली शीशियां, रबर और एल्युमीनियम के ढक्कन, प्लास्टिक की कीप, पाइप, नमक के पैकेट और एक ट्रांसपोर्ट वाहन शामिल है।

भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा : डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख सारस्वत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जमशेदपुर(झारखंड)/भाषा। नीति आयोग के सदस्य और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के पूर्व प्रमुख वी. के. सारस्वत ने बुधवार को कहा कि भारत अपने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा है।

सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला की पांचवीं प्लेटिनम जुबली व्याख्यान में भाग लेने के लिए इस्पात नगरी आए सारस्वत ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों का 70 प्रतिशत आयात करता था। डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख सारस्वत ने कहा, ''अब प्रवृत्ति उलट गई है और हम अपनी जरूरतों का 70 प्रतिशत उत्पादन स्वदेश में करते हैं।'' उन्होंने कहा कि एस-400 वायु रक्षा प्रणाली जैसे कुछ सैन्य साजोसामान को छोड़कर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किए गए अधिकांश हथियार और मिसाइलें - जैसे आकाश और

ब्रह्मोस - स्वदेश निर्मित थे। उन्होंने कहा, ''आज, देश सशस्त्र बलों की तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए, या जहां हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं है, हथियारों के आयात पर निर्भर है।'' उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में रक्षा उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता काफी बढ़ी है क्योंकि केंद्र निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। सारस्वत ने कहा कि वे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (सीएसआईआर-एनएमएल) के वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों से प्रसन्न हैं। सरकार ने निजी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

भाजपा नेता की हत्या मामले में सीबीआई के आरोपपत्र में तृणमूल विधायक, दो पार्षदों के नाम

भाजपा नेता की हत्या मामले में सीबीआई के आरोपपत्र में तृणमूल विधायक, दो पार्षदों के नाम

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के दौरान भाजपा नेता अविजित सरकार की हत्या के संबंध में आपराधिक साजिश और हत्या के लिए तृणमूल कांग्रेस विधायक परेश पॉल और पार्षदों - स्वप्न समद्दार और पापिया घोष के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

सोमवार को सियालदह के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल अपने दूसरे पूरक आरोपपत्र में सीबीआई ने मामले के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत 15 अन्य लोगों को भी नामजद किया है। सीबीआई के आरोपपत्र के बाद पॉल की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। प. बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद दो मई 2021 को कंकुरगाछी इलाके में अविजित सरकार की हत्या कर दी गई थी। सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर पश्चिम बंगाल पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली थी।

ओडिशा समेत तीन राज्यों में आतंक मचाने वाली बाघिन जीनत गर्भवती है : अधिकारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भुवनेश्वर/भाषा। सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान से निकलकर ओडिशा समेत पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में भटकने वाली बाघिन जीनत के गर्भवती होने की संभावना है। वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

बाघिन जीनत तीन राज्यों में भटकती रही और 23 दिनों के बाद पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले से उसे पकड़ लिया गया, जहां से उसे वापस सिमिलिपाल लाया गया। बाघिन को सिमिलिपाल में एक जनवरी को एक बाड़े में रखा गया, जहां उस पर कई सप्ताह तक नजर रखी गई। अधिकारी ने बताया, ''बाड़े में रहने के दौरान वह स्वस्थ और तंदुरुस्त पाई गई और 17 अप्रैल को जीनत को जंगल में छोड़ दिया गया।'' अधिकारी ने बताया, ''बड़े बाड़े में रहने के दौरान भी जीनत जंगली नर बाघ टी12 के प्रति आकर्षित हुई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए बाघिन को बाड़े से बाहर निकाल दिया गया। मई महीने के दूसरे सप्ताह में टी 12 बाघ के साथ उसके संसर्ग को थर्मल कैमरे में रिकार्ड कर लिया गया जो जमुना चारागाह में लगाए गए थे।'' जंगल में छोड़े जाने के बाद से जीनत अभ्यारण्य के मुख्य क्षेत्र में घूम रही है और चीतल, सांभर तथा जंगली सूअर का शिकार कर रही है। उन्होंने कहा, ''बाघिन पर 'ट्रैकिंग टीम' द्वारा 24 घंटे नजर रखी जा रही है। प्रत्येक टीम में चार लोग शामिल हैं और सैटेलाइट आधारित जीपीएस का उपयोग करके भी इसकी निगरानी की जा रही है।'' उन्होंने बताया, '' उसने संसर्ग बंद कर दिया है और खुद को एकांत में समेट लिया है जो गर्भवती होने का प्रमुख संकेत है।''

भारतीय के मुख्य फुटबॉल कोच मारक्वेज ने एआईएफएफ के साथ आपसी सहमति से पद छोड़ा

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रीय टीम के लगातार खराब प्रदर्शन के बाद आलोचनाओं का सामना कर रहे भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच मनोलो मारक्वेज ने बुधवार को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के साथ 'आपसी सहमति' पर पहुंचने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एआईएफएफ की कार्यकारी समिति ने यहां बैठक में मारक्वेज को पदमुक्त करने पर सहमति जताई क्योंकि उन्होंने अपने अनुबंध में एक साल बाकी रहने के बावजूद ऐसा करने की इच्छा जताई थी। एआईएफएफ के उप महासचिव के सत्यनारायण ने बताया, ''एआईएफएफ और मनोलो ने दोनों पक्षों पर कोई वित्तीय प्रभाव डाले बिना आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। इसलिए उन्हें भारत के कोच के पद से मुक्त कर दिया गया है।

तेजस्वी बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं : पाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने बुधवार को कहा कि राजद नेता तेजस्वी यादव की ''संशोधित वक्फ अधिनियम को कूड़ेदान में फेंकने'' की टिप्पणी बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को गुमराह करने का एक प्रयास है। वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पाल ने मुंबई में संवाददाताओं से कहा, ''तेजस्वी और ओवैसी के बीच प्रतिस्पर्धा है। वे मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में देखते हैं।''

तेजस्वी ने कहा था कि अगर बिहार में उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह संशोधित वक्फ अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक

देगी। पाल ने दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी इस कानून का विरोध कर रहे हैं, जबकि देश भर के गरीब और पसमांदा मुसलमान इसका समर्थन कर रहे हैं। पसमांदा एक व्यापक शब्द है जिसमें पिछड़े, दलित और आदिवासी मुसलमान शामिल हैं। पाल ने कहा कि इस अधिनियम का उद्देश्य जरूरतमंद मुसलमानों के लाभ के लिए वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करना है। उन्होंने कांग्रेस और राजद पर लोगों की भावनाओं से खेलने का आरोप लगाया और उन्हें चुनौती दी कि वे कानून में ऐसा कोई प्रावधान बताएं जिसमें मुसलमानों से वक्फ की जमीन लेकर दूसरों को देने का प्रावधान हो। तेजस्वी के 'कूड़ेदान' वाले बयान पर पाल ने कहा कि राजद नेता उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने अवैध रूप से वक्फ की जमीन हड़पी है।

भाजपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सच्चर समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू कर रही है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि वक्फ संपत्तियों से सालाना 12,000 करोड़ रुपए की आय हो सकती है।

बुमराह को बाहर बैठाने के भारत के फैसले से शास्त्री स्तब्ध

बर्मिंघम/भाषा। भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पूरी तरह से फिट जसप्रीत बुमराह को आराम देने के भारत के फैसले पर हैरानी जताई और कहा कि इस तेज गेंदबाज को एक महत्वपूर्ण मैच से बाहर बैठने का विकल्प नहीं दिया जाना चाहिए था।

पिछले साल अक्टूबर से टेस्ट क्रिकेट में खराब दौर से गुजर रहा भारत अपने पिछले नौ मैच में से सिर्फ एक जीत हासिल कर पाया है जो एक दशक से भी अधिक समय में उसका सबसे खराब प्रदर्शन है। शुभमन गिल की अगुआई वाली भारतीय टीम लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती टेस्ट में पांच विकेट से हार गई थी। शास्त्री ने 'स्काई स्पोर्ट्स' से कहा, ''अगर आप भारत के प्रदर्शन को देखें तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट मैच है। आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैच गंवाए, आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी तीन मैच गंवाए।'' उन्होंने कहा, ''आप यहां पहला टेस्ट मैच हार गए और आप जीत की राह पर वापस लौटना चाहते हैं। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा तेज गेंदबाज है और आप उसे सात दिन के ब्रेक के बाद बाहर बैठाते हैं, इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है।'' बुमराह ने लीड्स में पहले टेस्ट की पहली पारी में 14वीं बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट हासिल किए थे। बुधवार को टॉस के बाद गिल ने इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज माइकल आथर्टन से कहा कि बुमराह के गेंदबाजी को बोझ का प्रबंधन करने के लिए उन्हें आराम दिया गया है।

असम में अवैध मवेशी वध और गोमांस बेचने के आरोप में करीब 200 लोग गिरफ्तार

गुवाहाटी/भाषा। असम मवेशी संरक्षण अधिनियम के कथित उल्लंघन के सिलसिले में लगभग 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया और राज्य भर में 1.7 टन से अधिक संदिग्ध गोमांस जब्त किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) अखिलेश कुमार सिंह के अनुसार, मवेशियों के अवैध वध और रेस्तरां में अनधिकृत रूप से गोमांस बेचने की घटनाओं की जांच के लिए मंगलवार को पूरे असम में अभियान चलाया गया। उन्होंने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, अधिनियम के उल्लंघन के खिलाफ अभियान कल शुरू हुआ और हमने अब तक 196 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमने राज्य भर में विभिन्न स्थानों से 1,732 किलोग्राम संदिग्ध गोमांस भी जब्त किया है। सिंह ने बताया कि पिछले दो दिनों में पुलिस ने असम के लगभग सभी जिलों में 178 होटलों, रेस्तरां और बूचड़खानों की तलाशी ली है।

क्लासिकल शतरंज की तैयारी के लिए बहुत अधिक प्रयास की जरूरत होती है : प्रज्ञानानंदा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा का मानना है कि मैग्नस कार्लसन और हिकारू नाकामुरा जैसे खिलाड़ी धीरे धीरे क्लासिकल शतरंज से दूर हो रहे हैं जिसका कारण मानसिक और शारीरिक थकावट है जो लंबे समय तक लंबे प्रारूप में खेलने से आती है।

पांच बार के विश्व चैंपियन कार्लसन और दुनिया के दूसरे नंबर के अमेरिकी ग्रैंडमास्टर नाकामुरा ने कम क्लासिकल मैच खेले हैं जबकि इनका ध्यान फ्रीस्टाइल, रैपिड और ब्लिट्ज प्रारूपों पर रहा है। इस साल तीन मुख्य क्लासिकल खिताब जीतने वाले प्रज्ञानानंदा का मानना है कि खिलाड़ियों को क्लासिकल शतरंज के लिए लगने वाली घंटों की तैयारी पसंद नहीं है जिससे उन्हें रैपिड और ब्लिट्ज इससे अधिक संतोषजनक लगते हैं।

प्रज्ञानानंदा ने कहा, ''क्लासिकल शतरंज खेलना मुश्किल है क्योंकि हर कोई इसके लिए अच्छी तरह से तैयार होता है। क्लासिकल शतरंज में शुरुआती हिस्से की तैयारी बहुत अहम होती है। अगर आप इसकी तुलना फ्रीस्टाइल से करें तो आपको इससे पहले तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है जबकि क्लासिकल शतरंज में आपको तैयारी के लिए बाध्य होना पड़ता है। '' इस साल टाटा स्टील मास्टर्स, सुपरबेट क्लासिक और उज शतरंज कप जीतने वाले प्रज्ञानानंदा ने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि कोई भी यह प्रक्रिया पसंद करता है लेकिन आप मजबूर हैं और आपको हर चीज के लिए एक योजना बनानी होती है। इसके लिए काफी अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है।'' चेन्नई के 19 वर्षीय खिलाड़ी को लगता है कि वर्षों तक क्लासिकल शतरंज खेलने के साथ 'बर्नआउट' (थकान) की संभावना भी बढ़ जाती है। प्रज्ञानानंदा ने कहा, ''और जब आप बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट खेलते हैं तो आपकी ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। आप मानसिक और शारीरिक रूप से भी थक सकते हैं। इसलिए ये सभी चीजें होती हैं। मुझे लगता है कि यही कारण है कि हर कोई अन्य प्रारूपों को पसंद करता है। '' उन्होंने कहा, ''मुझे खुद फ्रीस्टाइल काफी पसंद है क्योंकि इसमें आपको खेल से पहले तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने खेल पर काम नहीं करना चाहते। हमें शतरंज पर काम करने में मजा आता है। '' प्रज्ञानानंदा ने कहा, ''लेकिन सच यह है कि आपको तैयारियों में काफी घंटे लगाने पड़ते हैं। आपको तीन-चार घंटे की तैयारी करनी पड़ती है और सभी को यह पसंद नहीं आता।

आषाढ़ शुक्ल - 8 ■ संवत 2082 ■ वर्ष - 20 ■ अंक - 334 ■ पृष्ठ - 8 ■ रु. 5/- बेंगलूरु » गुरुवार » 03-07-2025 ■ www.dakshinbharat.com ■ Email : news@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूरु और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

5 मैं पांच साल तक कर्नाटक का मुख्यमंत्री रहूंगा : सिद्दरामय्या

6 आतंकवाद पर भारत को वैश्विक मौन स्वीकार्य नही

7 पायल घोष ने बताया श्रीदेवी की कॉस्मेटिक सर्जरी का सच

फर्स्ट टेक

संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक

नई दिल्ली/भाषा। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक आहूत किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बुधवार को यह जानकारी दी। रीजीजू ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, राष्ट्रपति ने 21 जुलाई से 21 अगस्त, 2025 तक संसद का मानसून सत्र आहूत करने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर 13 और 14 अगस्त को कोई बैठक नहीं होगी। पहले यह सत्र 12 अगस्त को समाप्त होना था, लेकिन अब इसे एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है।

03-07-2025 सूर्यास्त 6:50 बजे | 04-07-2025 सूर्योदय 5:58 बजे

BSE	NSE
83,409.69	25,453.40
(-287.60)	(-88.40)

सोना	चांदी
10,014 रु.	109,575 रु.
(24 कैरेट) प्रति ग्राम	प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

कुटिल युग

चीत्कार कर रही द्रोपदियां,
हर ओर दुशासन घूम रहे।
अर्जुन बृहन्नला बने हुए,
समरांगण में मासूम रहे।
चुप बैठे भीष्म अपाहिज से,
शकुनी पांसों को चूम रहे।
यह दौर पुनः खुदगर्जी का,
सब अपने मद में झूम रहे।।

'आतंकवादियों का सफाया करने में संकोच नहीं करेगी मोदी सरकार'

सरगना और उन्हें प्रायोजित करने वाली सरकारों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार आतंकवादियों का सफाया करने में संकोच नहीं करेगी, चाहे वे कहीं भी हों, तथा सरगना और उन्हें प्रायोजित करने वाली सरकारों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा।

सिंह ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) की राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए, पड़ोसी देश का नाम लिए बिना पाकिस्तान को यह कड़ा संदेश दिया।

राज्य में आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं।

रक्षा मंत्री ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में, 'सर्जिकल स्ट्राइक' और बालाकोट हवाई हमले जैसे कदमों के साथ देश की सुरक्षा नीति में नया बदलाव आया है।

रक्षा मंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद चलाए गए सैन्य अभियान का जिक्र करते हुए कहा, ''ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहली बार हमने अपनी सीमा से 100 किलोमीटर दूर स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया। बेशक, हमने केवल उन लोगों पर हमला किया, जिन्होंने हम पर हमला किया था। यही कारण है कि किसी भी नागरिक या सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया।'' उन्होंने कहा, ''मोदी के नेतृत्व में, हमारी नीति आतंकवादियों को खत्म करने में संकोच न करने की रही है, चाहे वे कहीं भी हों। और हम यह आतंकवादी हमलों के सरगना और उन्हें प्रायोजित करने वाली सरकारों के बीच कोई भेद किए बिना करेंगे।''

सिंह ने कहा कि मोदी के ''स्वदेशीकरण'' और ''आत्मनिर्भर भारत'' पर जोर देने के कारण देश के रक्षा निर्यात में तेज वृद्धि देखी गई है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''मोदी सरकार दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ काम करती है, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत सरकारों से बिल्कुल अलग है, जिनमें दिशाहीनता थी और जो वोट बैंक की चिंता से प्रेरित थीं।''

सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले की टिप्पणी पर उठे विवाद का भी परोक्ष संदर्भ दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना से 'पंथनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्दों को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था।

यात्रा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को दो दिवसीय यात्रा पर घाना पहुंचे, जहां वह पश्चिम अफ्रीकी देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ वार्ता करेंगे और मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा करेंगे। घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने प्रधानमंत्री मोदी की हवाई अड्डे पर अगवानी की, जहां उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की घाना की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। साथ ही, यह तीन दशकों में भारत के किसी प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा है। मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''घाना के अक्करा पहुंचा। राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा द्वारा हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत किये जाने से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। दोनों देश अपने दीर्घकालिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नये रास्ते तलाशने के लिए मिलकर काम करने को तत्पर हैं।'' राष्ट्रपति महामा के निमंत्रण पर घाना की यात्रा पर आए मोदी का भव्य स्वागत किया गया, जिस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सलामी गारद का निरीक्षण किया।

'क्वाड' ने बिना किसी देरी के पहलगाम हमले के दोषियों को दंडित करने का आह्वान किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

ऊचटएगटन/भचऋच। चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद समूह 'क्वाड' ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की साजिश रचने वालों, उसे अंजाम देने वालों और इसके वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के न्याय के कठघरे में लाने का आह्वान किया तथा संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से इस संबंध में सहयोग बढ़ाने की अपील की।

चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद (क्वाड) के सदस्य देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के विदेश मंत्रियों ने इस वर्ष के अंत में भारत में होने वाले समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक एजेंडा तय करने के वास्ते मंगलवार को अमेरिका की राजधानी में बैठक की।

'क्वाड' सदस्य देशों ने 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया। पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए थे। हालांकि, संयुक्त बयान में मंत्रियों ने पाकिस्तान का या मई में भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच चार दिन तक चले सैन्य संघर्ष का जिक्र नहीं किया।

बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान में उनके समकक्ष ताकेशी इवाया शामिल हुए। 'क्वाड' देशों के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की ''कड़े से कड़े शब्दों में'' निंदा की, जिसमें 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया कि

2000 करोड़ रुपए की एजेएल कंपनी को हड़पना चाहते थे सोनिया और राहुल गांधी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी 2,000 करोड़ रुपये की कंपनी 'एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड' (एजेएल) की संपत्ति हड़पना चाहते थे।

यह कंपनी नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशक है।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने नेशनल हेराल्ड मामले में संज्ञान के बिंदुओं पर दलीलें सुन रहे थे।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू ने कहा कि 'यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड' नामक कंपनी बनाने की साजिश रची गयी थी, ताकि एजेएल की संपत्ति हड़पी जा सके। एजेएल ने करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) से 90 करोड़ रुपये कर्ज लिये थे। यंग इंडियन में सोनिया और राहुल के पास 76 प्रतिशत शेयर थे।

राजू ने साजिश का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा, ''एजेएल मुनाफा नहीं कमा रही थी, लेकिन उसके पास 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति थी। इसके बावजूद उसे अपने दैनिक कामकाज को संभालना मुश्किल हो रहा था।'' उन्होंने आगे कहा, ''साजिश 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति हड़पने के लिए यंग इंडियन का निर्माण करना था। सोनिया और राहुल गांधी इस 2,000 करोड़ रुपये की कंपनी को अपने कब्जे में लेना चाहते थे।''

राजू ने कहा कि यंग इंडियन के निदेशक के रूप में राहुल की नियुक्ति के छह दिनों के भीतर ही इसने एजेएल को ऋण चुकाने या इसे इक्विटी में बदलने के लिए एक प्रतिवेदन भेजा।

न्यायाधीश गोगने ने राजू से पूछा कि क्या एआईसीसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तरह एजेएल के ऋण को माफ कर सकती है।

एएसजी ने कहा कि इस मामले में एजेएल के पास 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति थी, जिसे उन्होंने 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले दे दिया।

न्यायाधीश ने राजू से फिर पूछा कि क्या राजनीतिक दलों के लिए अखबार का स्वामित्व रखना अजीब बात है।

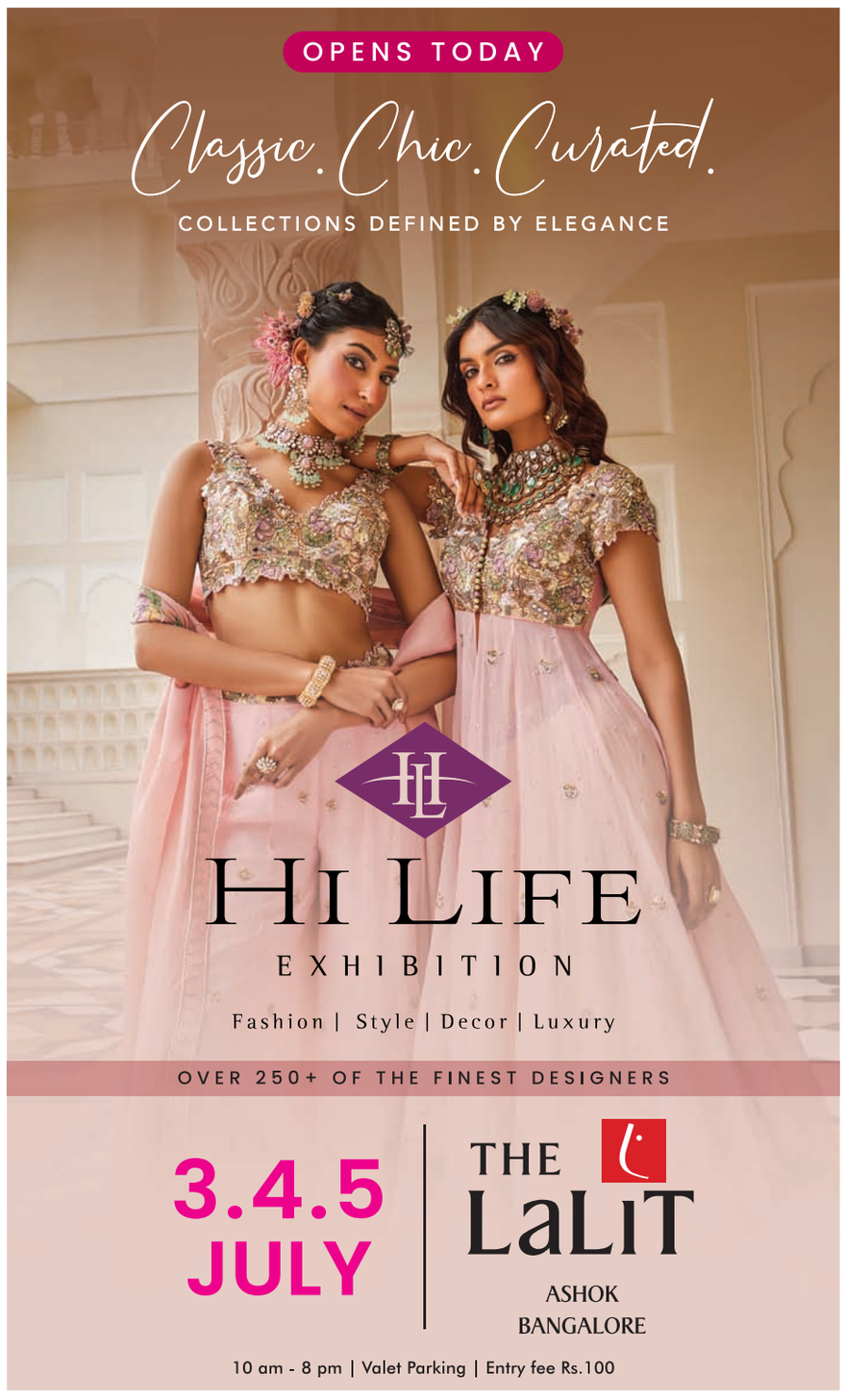

हसीना को छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई

ढाका/भाषा। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना के मामले में बुधवार को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने छह महीने की जेल की सजा सुनाई। स्थानीय मीडिया ने यह खबर दी। 'ढाका ट्रिब्यून' अखबार ने कहा कि न्यायाधीश मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार की अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-1 की तीन सदस्यीय पीठ ने यह फैसला जारी किया।

गिल का बतौर कप्तान लगातार दूसरा शतक, भारत के पांच विकेट पर 310 रन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बर्मिंघम/भाषा। कप्तान शुभमन गिल की संयम से भरी लगातार दूसरी शतकीय पारी के दम पर भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन बुधवार को पांच विकेट पर 310 रन बना लिये।

कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह के बगैर अंतिम एकादश में तीन हरफनमौलाओं को लेकर उतरी भारतीय टीम ने बल्लेबाजी में संतुलित प्रदर्शन किया। लीड्स की ही तरह एडबस्टन की पिच भी बल्लेबाजों की मददगार है और बुमराह की गैर मौजूदगी में भारत को कम से कम 500 रन का स्कोर बनाना होगा।

पहले दिन का खेल समाप्त होने पर गिल 216 गेंद में 114 और रविंद्र जडेजा 67 गेंद में 41 रन बनाकर खेल रहे हैं। गिल ने शोएब बशीर को लगातार स्वीप शॉट खेलकर अपना शतक पूरा किया। वह और जडेजा छठे विकेट की अटूट साझेदारी में 99 रन बना चुके हैं।

पहले टेस्ट में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले ऋषभ पंत ने 42 गेंद में 25 रन बनाये जबकि शार्दुल ठाकुर की जगह चुने गए नीतिश कुमार रेड्डी एक ही रन बना सके। अंतिम सत्र में ये दोनों बल्लेबाज आउट हुए।

पंत को बशीर ने लांग आन पर जैक क्रॉली के हाथों लपकवाया। वहीं रेड्डी को क्रिस वोक्स ने बोल्ड किया।

इससे पहले यशस्वी जायसवाल शतक से चूक गए। दूसरे सत्र में स्टोक्स ने जायसवाल को शॉर्ट और वाइड गेंद पर विकेट के पीछे जैमी स्मिथ के हाथों लपकवाया।

जायसवाल ने 107 गेंद में 13 चौकों की मदद से 87 रन बनाये।

भारत ने दूसरे सत्र में 28 ओवर में जायसवाल का विकेट खोकर 84 रन बनाये।

।। श्री जयमल्लाय नमः ।। ।। श्री महावीराय नमः ।। ।। जय गुरु पार्श्व-पद्म ।।

श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ
हलसूरु, बेंगलूरु

चातुर्मास प्रवेश
शुक्रवार दि. 4.7.2025

आदरणीय धर्मनिष्ठ स्वजन, सादर जय जिनेन्द्र !

अत्यंत हर्ष के साथ सेवा में निमंत्रण भेज रहे हैं कि बेंगलुरु एवं हलसुरु संघ को असीम पुनवानी से इस वर्ष जयगच्छाधिपति, वचन सिद्ध साधक, आशुकवि, बारहवें पट्टधर आचार्य प्रवर 1008 पू. श्री पार्श्वचन्द्रजी म.सा. की आज्ञानुवर्तिनी गुरुवर्या श्री सुगनकंवरजी म.सा. की सुशिष्याएं सरलमना महासतीजी श्री शशिप्रभाजी म.सा., परम विदुषी तपस्वीनी महासतीजी श्री इन्दुप्रभाजी म.सा., मधुर व्याख्यानी महासतीजी श्री निपुणप्रभाजी म.सा., प्रवचन प्रभाविका महासतीजी श्री वृद्धिप्रभाजी म.सा., मधुर गायिका महासतीजी श्री रिद्धिप्रभाजी म.सा. ठाणा 5 के वर्षावास 2025 का लाभ हलसुरु श्री संघ को प्राप्त हुआ हैं। हमारे संघ में हर्ष, उल्लास, उमंग, उत्साह की लहर वर्द्धमान हैं। इस अनमोल कृपा महर के लिये हम आचार्य भगवंत के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

पधारो ! पधारो ! पधारो ... हमारे प्रांगण में !

पूज्य महासतियाँजी शुभ दि. 4.7.2025 शुक्रवार प्रातः ठीक 7:35 बजे चोरड़िया निवास, 1301, 13th क्रास, इन्दिरानगर से जयघोषों के साथ चातुर्मास हेतु विहार कर महावीर भवन, हलसुरु पधारेंगे। जिनशासन प्रभावना के महोत्सव पर आप सपरिवार, सकल संघ पधार कर अनुग्रहित करें।

प्रवचन : दिनांक 10.07.2025 से प्रातः 9:15 से 10:15 बजे तक

निवेदक : श्री श्वे. स्था. जैन श्रावक संघ, हलसूरु, बेंगलूरु

अध्यक्ष :	मंत्री :	कोषाध्यक्ष :
धनपतराज बोहरा	अभयकुमार बांठिया	दिलीपकुमार गादिया
94482 64745	93412 18945	98457 87770

संपर्क सूत्र : उगमराज मूथा 9844045077, उत्तमचंद तातेड़ 9448003611

समस्त कार्यकारिणी, समस्त संघ, महिला मंडल, श्री जैन युवक संघ, नवकार बहु मंडल, बालक मंडल, बालिका मंडल, हलसूरु, बेंगलूरु

समारोह के पश्चात अल्पाहार की व्यवस्था है। कृपया अतिथि सत्कार का अवसर प्रदान करें।

कोटा में मूसलधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त : बैराज के गेट खुले, घर-स्कूल-हॉस्पिटल जलमग्न

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोटा। शहर में मंगलवार रात से जारी मूसलधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। देर रात 11 बजे शुरू हुई तेज बारिश का असर इतना जबरदस्त रहा कि शहर के कई इलाकों में सड़कों पर नदियाँ बहने लगीं और लोगों के घरों से लेकर स्कूल, अस्पताल और सरकारी कार्यालय तक पानी में डूब गए। चंबल नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए कोटा बैराज के पांच गेट खोल दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार बैराज से करीब 75,186 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसमें चार गेट 15-15 फीट और एक गेट 5 फीट तक खोला गया है। बैराज की क्षमता 854 फीट है, जबकि वर्तमान में इसका जलस्तर 852.80 फीट तक पहुंच चुका है। इसी के चलते जवाहर सागर डैम से भी 46 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।

लगातार बारिश के कारण शहर का मौसम एकदम बदल गया है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। इससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत जरूर मिली, लेकिन दूसरी ओर जलभराव और अव्यवस्थाओं ने मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं।

कोटा जिले के मोड़क कस्बे में स्थिति बेहद चिंताजनक है। चौसला रोड और ईदगाह के पास करीब 50-60 घरों में पानी घुस गया है। इन इलाकों में सड़कें तालाब जैसी नजर आ रही हैं। रामपुरा इलाके की गलियों में बारिश के पानी ने नदियों जैसा बहाव बना लिया है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बारिश की वजह से सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल और पुलिस चौकी के बाहर भी जलजमाव की स्थिति है। न सिर्फ बाहर की सड़कें बल्कि कई संस्थानों के प्रवेश द्वार तक पानी घुस चुका है। अस्पताल आने-जाने वाले मरीज और स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राएं भारी परेशानी में हैं।

सीएडी कॉलोनी में सरकारी क्वार्टर्स के बाहर और भीतर पानी भर गया है। चेंबर ओवरफ्लो होने की वजह से गंदा पानी घरों में घुस गया है। कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन को शिकायत दी थी, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इससे नाराज लोगों में रोष है। शहर के अंडरपास और प्रमुख सड़कों पर पानी भर गया है। कई इलाकों में वाहन बंद पड़ गए हैं और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। रुक-रुक कर हो रही बारिश ने राहत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। मौसम विभाग ने कोटा सहित 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि आने वाले घंटों में और अधिक भारी बारिश हो सकती है।

विभाग ने लोगों को सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। साथ ही जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की चेतावनी दी है। यहालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जलभराव वाले इलाकों में पंप और राहत दलों को रवाना किया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि मौके पर कोई मदद नहीं पहुंची। शहर के कई हिस्सों में बिजली की आपूर्ति भी बाधित हुई है।

राजस्थान में हथियारों का जखीरा बरामद, कुख्यात बदमाश सहित दो गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) और प्रतापगढ़ जिला पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में अवैध हथियारों के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इनसे 14 अवैध विदेशी और देशी हथियार, 1860 कारतूस और 10 मैगजीन का विशाल जखीरा बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में दो प्रमुख अपराधियों कुख्यात गैंगस्टर सलमान खान (38) और उसे हथियार आपूर्ति करने वाले राकेश कुमार (48) को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त महानिदेशक (एजीटीएफ) दिनेश एमएन ने बुधवार को बताया कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ भेजे गए दलों द्वारा व्यापक खुफिया जानकारी जुटाने के साथ उप महानिरीक्षक योगेश यादव की देखरेख में अभियान की योजना बनाई गई थी।

उन्होंने बताया कि 28 जून को छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने राकेश कुमार को छोटी सादड़ी-नीमच रोड से एक पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया कि राकेश, अवैध हथियार आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण मोहरा था और उसकी गिरफ्तारी इस अभियान की पहली कड़ी साबित हुई। उन्होंने बताया कि राकेश से हुई पूछताछ ने पुलिस को अपराध की दुनिया के एक और बड़े नाम सलमान (38), निवासी नागदा, उज्जैन तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि सलमान फिरौती के एक मामले में पहले से ही बांसवाड़ा जेल में बंद था। उन्होंने बताया कि एजीटीएफ ने उसे 'प्रोटेक्शन वारंट' पर लिया।

अधिकारी ने बताया कि पूछताछ में सलमान ने बताया कि उसके पिता शेरखान पठान भी पुलिसकर्मी थे लेकिन हत्या सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे और अंततः पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। अधिकारी ने बताया कि सलमान ने कबूल किया कि उसने भी कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। अधिकारी के अनुसार सलमान ने बताया कि स्कूल छोड़ने के बाद वह लड़ाई-झगड़ों में लिप्त हो गया और अपनी 90 बीघा पैतृक जमीन होने के बावजूद प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर विवादित जमीनों पर कब्जा करने लगा।

अधिकारी के अनुसार सलमान ने बताया कि अपने खिलाफ लगातार बढ़ते मुकदमों से बचने के लिए उसने निवास बदलकर फर्जी पासपोर्ट बनवाया और दुबई भाग गया था। अधिकारी के अनुसार पुलिस को सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह मिली कि दुबई जाने से पहले उसने अपने सभी अवैध हथियार दोस्त मोहम्मद नवाज, निवासी रतलाम के पास 30 लाख रुपये की जमानत के तौर पर गिरवी रख दिए थे, उसका इरादा था कि जेल से छूटने के बाद वह इन्हें वापस ले लेगा। पुलिस ने बताया कि सलमान के खुलासे के बाद छोटी सादड़ी में हथियारों का बड़ा जखीरा जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि सलमान खान पर हमला, जबरन वसूली, चोरी, हत्या के प्रयास सहित कई मामले दर्ज हैं।

भजनलाल ने गुरू पूर्णिमा महोत्सव के पोस्टर का किया विमोचन

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजधानी जयपुर के मानसरोवर में अनोखी धाम में दस जुलाई को आयोजित होने वाले गुरू पूर्णिमा महोत्सव के पोस्टर का बुधवार को यहां विमोचन किया। शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर इस पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान अनोखी धाम सेवा समिति के अध्यक्ष विनय कुमार शर्मा सहित प्रतिनिधिमंडल के सदस्य मौजूद थे। अनोखी धाम सेवा समिति द्वारा दस जुलाई को मानसरोवर की पत्रकार कॉलोनी के अनोखी धाम (हनुमंत स्वरूप नीब करौरी महाराज) में गुरू पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।

'एक पेड़ मां के नाम अभियान' में ऊर्जा विभाग के कार्मिक भी देंगे योगदान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। 'एक पेड़ मां के नाम-हरयालो राजस्थान वृक्षारोपण महाभियान ' में ऊर्जा विभाग भी अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता निभाएगा। मानसून के दौरान प्रदेशभर में विभाग की ओर से थर्मल इकाइयों, ग्रिड सब स्टेशनों, कार्यालय परिसरों आदि में वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने बुधवार को सेन्ट्रल पार्क में पौधारोपण के बाद यह बात कही।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के माध्यम से देशवासियों को प्रकृति से जोड़ने का महत्ती संकल्प लिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'एक पेड़ मां के नाम-हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण महाभियान' के माध्यम से प्रदेश को हरा-भरा बनाने में जन-जन से भागीदारी का आह्वान किया है।

नागर ने कहा कि ऊर्जा विभाग के कार्मिक अधिक से अधिक पौधे लगाकर शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति में अपना योगदान देंगे। ऊर्जा मंत्री के साथ ही विभाग के कार्मिकों ने भी इस दौरान गुलमोहर, आम आदि के पौधे लगाए।

मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए मंत्री ने पुख्ता प्रबंधन करने के दिए निर्देश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में मानसून का दौर प्रारंभ हो चुका है। इसे देखते हुए सभी जिलों में मौसमी बीमारियों पर रोकथाम, जांच एवं उपचार के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। जिन जिलों में बारिश अधिक हो रही है, वहां विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि मौसमी बीमारियों के केस नियंत्रण में रहें। चिकित्सा मंत्री बुधवार को स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियों सहित अन्य विषयों पर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने संभाग एवं जिला स्तरीय अधिकारियों से चर्चा कर मौसमी बीमारियों की स्थिति की जानकारी ली और आवश्यक दिशानिर्देश दिए। खींवसर ने कहा कि विगत वर्ष मौसमी बीमारियों पर प्रभावी रोकथाम की गई थी, जिसके चलते केसों की संख्या कम रही और मौतें भी नगण्य रहीं। इस वर्ष भी माकूल प्रबंधन करते हुए मौसमी बीमारियों के प्रसार पर नियंत्रण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी मानव संसाधन की और आवश्यकता है, तत्काल अवगत कराएं। अस्पतालों में दवाओं की समुचित उपलब्धता और जांच उपकरणों की क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मौसमी बीमारियों के बारे में नियमित रूप से रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए। साथ ही, राज्य एवं जिला स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

खींवसर ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत प्रदेशभर में स्वीकृत नए चिकित्सा संस्थानों के लिए भूमि आवंटन की कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित जिला कलक्टर के माध्यम से जमीन आवंटन की कार्यवाही को पूरा कराने में गंभीरता बरतें, ताकि नए संस्थानों के भवनों का जल्द निर्माण हो और प्रदेश में स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा मजबूत हो। चिकित्सा मंत्री ने टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की समीक्षा करते हुए प्रदेश की अधिकाधिक ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग, जांच एवं उपचार गतिविधियां व्यापक स्तर पर संचालित हो। आमजन को जागरूक कर प्रदेश को टीबी मुक्त बनाएं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने कहा कि सभी अधिकारी फील्ड में एक्टिव रहकर स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। सीएमएचओ यह ध्यान रखें कि चिकित्सा संस्थानों में जांच एवं उपचार की व्यवस्थाओं में किसी तरह की कमी नहीं रहे। दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता हो और स्टाफ अनुपस्थित नहीं रहे। श्रीमती राठौड़ ने कहा कि अब आरजीएचएस योजना का संचालन चिकित्सा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। सभी चिकित्सक रोगियों के उपचार में नियमों का पालन करें और दवाएं एवं जांचें लिखने में पूरी पारदर्शिता बरतें। किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना की राज्य स्तर से गहन मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव ने जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, ट्रोमा सेंटर एवं एमसीएच सेंटर के नए भवनों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन का कार्य टाइम बाउंड अवधि में पूर्ण कर लिया जाए।

जिन चिकित्सा संस्थानो के भवनों का निर्माण कार्य 70 प्रतिशत से अधिक हो चुका है, वहां चिकित्सा उपकरणों, फर्नीचर सहित विभिन्न आवश्यकताओं का गैप असेसमेंट कर अनुमानित बजट के लिए मांग समय पर निदेशालय भिजवाएं। उन्होंने आईपीएचएल लैब, एसडीएच व मॉडल सीएचसी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जांच सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया।

दीया कुमारी ने बारिश से जुड़ी समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को यहां जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निदान के निर्देश दिए। इस दौरान विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए नागरिकों ने अपने मुद्दे और समस्याएं उनके समक्ष रखीं। जनसुनवाई में खास तौर पर बारिश के कारण उत्पन्न हो रही समस्याएं जैसे जलभराव, सड़कों की क्षति और नालों की सफाई को लेकर कुछ शिकायतें सामने आईं। उन्होंने इन विषयों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मानसून के दौरान कई शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव एवं अव्यवस्थित ड्रेनेज जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। आज की जनसुनवाई में भी इस तरह के कई मामले आए, जिन पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने जनसुनवाई को आमजन से सीधे संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए कहा कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रत्येक शिकायत का समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। थोड़ी बहुत कुछ शिकायतों के अलावा जनसुनवाई में आए लोगों ने कई समाधानों के लिए धन्यवाद भी दिया।

तीन बाघों की हड्डियां मिलने से रणथंभौर में शिकार को लेकर चिंताएं बढ़ीं

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। शिकारियों के एक अंतरराज्यीय गिरोह द्वारा मारे गए तीन बाघों के रणथंभौर बाघ अभयारण्य (आरटीआर) से होने की आशंका के बाद राजस्थान के इस विख्यात अभयारण्य में शिकार को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने मध्य प्रदेश की 'स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स', राजस्थान वन विभाग और सवाई माधोपुर के एक गैर सरकारी संगठन 'टाइगर वॉच' के एक संयुक्त अभियान के बाद यह खुलासा हुआ। इसके तहत छह शिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार शिकारियों में तीन राजस्थान से हैं।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार पांच जून को मध्य प्रदेश के श्योपुर के पास बाघों की हड्डियों के 225 से अधिक टुकड़े जब्त किए गए थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में राजस्थान के दौसा के निवासी दाऊजी भील और सुनीता दाऊजी और मध्य प्रदेश के श्योपुर के बेस्ता भील शामिल हैं। इनके पास बाघों की खोपड़ी और हड्डियां मिलीं। मध्य प्रदेश के वन अधिकारियों ने शिवपुरी से बानीराम मोघिया और नरेश तथा राजस्थान के टोंक निवासी राजाराम मोघिया को भी पकड़ा। एक आधिकारिक संवाद में मध्य प्रदेश के वन अधिकारियों ने राजस्थान से रणथंभौर के बाघों की डीएनए प्रोफाइल साझा करने को कहा है ताकि जब्त किए गए अवशेषों से इनका मिलान किया जा सके।

राजस्थान वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमें पत्र मिला है और समुचित परख के बाद जवाब दिया जाएगा। हमारी टीम इस पर सक्रियता से काम कर रही हैं। रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर अनूप के आर ने राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को एक रिपोर्ट भेजी है। इसमें कहा गया है, कुछ हड्डियां, बाघ की होना पाया गया है। ये हड्डियां किसकी हैं, यह पता लगाने के लिए आगे की जांच हेतु मध्य प्रदेश और राजस्थान वन विभागों की संयुक्त टीम समन्वय में काम कर रही है।

मध्य प्रदेश के जबलपुर में डीएनए परीक्षण से पुष्टि हुई कि जब्त किए गए अवशेष तीन बाघ और एक तेंदुए के हैं। नमूनों को रणथंभौर के बाघ डेटाबेस के साथ मिलान के लिए राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र (एनसीबीएस) बेंगलूरु भेजा गया है। वन अधिकारियों ने बताया कि रिपोर्ट तीन सप्ताह में आने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार यह शिकार चंबल के राजस्थान की ओर वाले इलाके में होने का संदेह है। सूत्रों ने बताया कि जांच में पता चला है कि करीब छह महीने पहले एक बाघ और होली के आसपास एक तेंदुआ मारा गया था। सूत्रों ने बताया कि ये दोनों घटनाएं राजस्थान में होने की आशंका है।

वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने मांग की है।

बाड़मेर में एक ही परिवार के चार सदस्यों ने आत्महत्या की

जयपुर। राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक ही परिवार के चार सदस्यों ने पानी के टांके (टंकी) में कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह घटना मंगलवार शाम को शिव थाना क्षेत्र के उण्डू गांव में ब्राह्मणों की ढाणी की है जहां शिवलाल (35), उनकी पत्नी कविता (32) और उनके आठ वर्षीय तथा छह वर्षीय दो बेटे घर के बाहर एक टैंक में मृत पाए गए।

प्रारंभिक जांच के अनुसार शिवलाल ने कथित तौर पर घर पर ताला लगाने के बाद अपने परिवार के साथ टांके में छलांग लगा दी। पुलिस नेन बताया कि शिवलाल के छोटे भाई ने उन्हें कई बार फोन किया, लेकिन जब फोन नहीं उठाया तो घटना की जानकारी हुई जिसके बाद पुलिस को सतर्क किया गया। शिव के पुलिस उपाधीक्षक मानाराम गर्ग ने कहा, शव मंगलवार शाम को टांके में मिले। महिला के पीहर पक्ष को सूचित किया गया और बुधवार सुबह उनकी मौजूदगी में शवों को निकाला गया क्योंकि वे रात में नहीं आ सके। कविता के चाचा गोपीलाल ने संवाददाताओं से कहा, शिवलाल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत राशि से अलग मकान बनाना चाहता था। लेकिन उसके भाई और मां ने इसकी अनुमति नहीं दी। इससे परेशान होकर उसने 29 जून को सुसाइड नोट लिखा। परिवार के अनुसार शिवलाल ने दो दिन पहले कथित नोट लिखा लेकिन उसने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन मंगलवार को जब उसकी मां बाड़मेर में अपने भाई से मिलने चली गई और उसके पिता धार्मिक कार्य के लिए बाहर गए तो शिवलाल और कविता ने अपने फोन बंद कर दिए और कथित तौर पर यह कदम उठाया। पुलिस ने दोनों पक्षों के रिश्तेदारों के बयान दर्ज किए और अधिकारियों ने कहा कि वे आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित धाराओं के तहत घरेलू उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रहे हैं। शिव पुलिस ने बताया कि कथित सुसाइड नोट और पारिवारिक विवादों को भी जांच का हिस्सा माना जाएगा।

डायलाना में आचार्यश्री अरविंदसागरसूरी के चातुर्मास को लेकर विशेष उत्साह

रविवार को आचार्यश्री का चातुर्मास प्रवेश

डायलाना। राजस्थान के गोड़वाड़ क्षेत्र के डायलाना ग्राम में शांतिनाथ आदिनाथ जैन संघ के तत्वावधान में आचार्यश्री अरविंदसागरसूरीश्वरजी आदि साधु साध्वियों का चातुर्मास प्रवेश रविवार को सुबह 7 बजे होगा। चातुर्मास के मुख्य लाभार्थी सिल्वर एम्पोरियम के संघवी शकुनदेवी मुलतानमल सुंदेशा मेहता परिवार ने बताया कि डायलाना में आचार्यश्री के पहले चातुर्मास को लेकर विशेष उत्साह है। गांव के विभिन्न जैन समुदाय सहित अन्य लोग भी कृत्रिम हस्तिापुर नगरी में चातुर्मास प्रवेश की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बेंगलूरु, मुम्बई, चेन्नई व अन्य शहरों से बड़ी संख्या में गुरुभक्त आचार्यश्री के चातुर्मास प्रवेश में शामिल होंगे।

सहायक नगर नियोजक रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक टीम ने राजस्थान के नागौर में एक सहायक नगर नियोजक को बुधवार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि नगर परिषद नागौर के एटीपी कौशल कुमार को चार लाख रुपये की कथित रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है।स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि परिवादी ने शिकायत की थी कि उसके भतीजे के नाम पंजीकृत 'वेयर हाउस व कोल्ड स्टोरेज' की तकनीकी रिपोर्ट अनुकूल बनाने की एवज में पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है।

सुरजेवाला कर्नाटक में सिद्दरामय्या के 'इस्तीफे की तैयारी' करने के लिए आए हैं : विजयेंद्र येडीयुरप्पा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष विजयेंद्र येडीयुरप्पा ने बुधवार को दावा किया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या के ''इस्तीफे की तैयारी'' करने के लिए राज्य में आए हैं। विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि राज्य का प्रशासनिक तंत्र ध्वस्त हो चुका है और शासन व्यवस्था अव्यवस्थित हो चुकी है। कांग्रेस विधायकों के बीच आपसी लड़ाई बढ़ती जा रही है और विकास कार्य ठप हो गए हैं।

विजयेंद्र ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पिछले कुछ दिनों से बेंगलूरु में हैं। वह यहां क्यों हैं। उन्हें भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के पतन की कोई चिंता नहीं है।'' उन्होंने दावा किया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विधायकों की राय ले रहे हैं और सिद्दरामय्या को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए आधार तैयार कर रहे हैं। शीर्ष पद के लिए लड़ाई तेज हो गई है जिसके कारण राज्य में खरीद-फरोख्त की संभावना है। रामनगर के विधायक इकबाल अंसारी के हाल के बयान का जिक्र करते हुए कि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार को 100 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, इस पर भाजपा के प्रदेश प्रमुख ने कहा कि बी. आर. पाटिल और राजू कागे सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी सिद्दरामय्या के खिलाफ बात की है।

उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों का विश्वास खो दिया है। विजयेंद्र ने राज्यपाल से स्थिति पर ध्यान देने का आग्रह किया। भाजपा नेता ने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया और उस पर बड़े पैमाने पर ''भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता'' का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की विफलताओं के कारण किसानों, अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा आत्महत्या करने के मामले बढ़ रहे हैं।

विजयेंद्र ने कहा कि यहां तक कि कांग्रेस विधायक भी निजी तौर पर इस गड़बड़ी को स्वीकार करते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा वाल्मीकि विकास निगम घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने के फैसले को उन्होंने भाजपा की महत्वपूर्ण जीत बताया।

उन्होंने आरोप लगाया कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्धारित 187 करोड़ रुपये पड़ोसी राज्य तेलंगाना में भेज दिए गए और संपत्ति, आभूषण खरीदने तथा चुनाव खर्च के लिए इसका दुरुपयोग किया गया। विजयेंद्र ने दावा किया कि सिद्दरामय्या को भाजपा के दबाव में मंत्री बी. नागेंद्र को मंत्रिमंडल से हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उन्हें फिर से शामिल करने के प्रयास अभी भी किए जा रहे हैं।

मेरे पास क्या विकल्प है? मुझे उनके साथ खड़ा होना होगा : डीके शिवकुमार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/चिक्कबल्लापुर। पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए कर्नाटक का मुख्यमंत्री बने रहने के सिद्दरामय्या के बयान के बाद उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है और वह सिद्दरामय्या का समर्थन करेंगे। शिवकुमार ने उनके पास कोई विकल्प नहीं होने का संकेत देते हुए कहा कि वह कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों का पालन करेंगे। शिवकुमार ने मुख्यमंत्री के बयान के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में यहां संवाददाताओं से कहा, ''मेरे पास क्या

विकल्प है? मुझे उनके साथ खड़ा होना है, उनका (सिद्दरामय्या) समर्थन करना है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी आलाकमान जो भी कहेगा और जो भी चाहेगा, उसे माना जाएगा।'' जब उनसे यह पूछा गया कि क्या पार्टी उनका समर्थन नहीं कर रही जबकि उनके समर्थक पार्टी के लिए उनके बलिदान का हवाला देते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, उन्होंने कहा, ''मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। लाखों कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी का समर्थन किया है। यह केवल डी के शिवकुमार की बात नहीं है।'' इससे पहले सिद्दरामय्या ने बुधवार को चिक्कबल्लापुर में कहा कि वह पांच साल के पूरे कार्यकाल के दौरान पद पर बने रहेंगे। राजनीतिक हलकों में, विशेषकर सत्तारूढ़ कांग्रेस में, सिद्दरामय्या और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के बीच सत्ता-साझाकरण समझौते का हवाला देते हुए इस वर्ष के अंत में मुख्यमंत्री बदले जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं।

मई 2023 में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्दरामय्या एवं शिवकुमार के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी और कांग्रेस शिवकुमार को मनाने में कामयाब रही तथा उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया। उस समय कुछ खबरें थीं कि ''क्रमिक मुख्यमंत्री फॉर्मूला'' के आधार पर समझौता हुआ है जिसके अनुसार शिवकुमार ढाई साल बाद मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन पार्टी द्वारा इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। शिवकुमार ने इससे पहले दिन में कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर कोई असंतोष नहीं है और जब सिद्दरामय्या राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो नेतृत्व के मुद्दे पर किसी विवाद की जरूरत नहीं है।

कांग्रेस की कर्नाटक इकाई में कोई असंतोष नहीं : शिवकुमार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर कोई असंतोष नहीं है और जब सिद्दरामय्या राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो नेतृत्व के मुद्दे पर किसी विवाद की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष शिवकुमार ने यह स्पष्ट किया कि पार्टी अनुशासन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी से उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं कहा है। शिवकुमार ने चेतावनी दी कि नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर सार्वजनिक बयान देने वाले नेताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्होंने रामनगर से विधायक एच.ए. इकबाल हुसैन को मंगलवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया जो यह बयान दे रहे हैं कि शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए।

शिवकुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''मैंने उन्हें नोटिस दिया है। दूसरों को भी नोटिस देना पड़ेगा। अनुशासन महत्वपूर्ण है। मैंने किसी से मेरा नाम लेने या मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं कहा है। इसकी कोई जरूरत

नहीं है। जब मुख्यमंत्री (सिद्दरामय्या) हैं, तो किसी विवाद की कोई जरूरत नहीं है।'' उनके समर्थक विधायक शिवकुमार की कड़ी मेहनत का हवाला देते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। शिवकुमार ने इस बारे में सवाल किए जाने पर कहा, ''सभी ने कड़ी मेहनत की है। मेरे जैसे सैकड़ों लोगों ने कड़ी मेहनत की है। क्या मैं अकेला हूं? लाखों पार्टी कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है। हमें पहले उनके बारे में सोचना होगा।'' इस बीच, कर्नाटक के प्रभारी कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लगातार तीसरे दिन पार्टी विधायकों के साथ आमने-सामने की अपनी बैठकें जारी रखीं। यह पूछे जाने पर कि क्या सुरजेवाला की बैठकों से पार्टी में असंतोष कम होगा, शिवकुमार ने कहा, ''पार्टी में कोई असंतोष नहीं है। वह (सुरजेवाला) पार्टी और संगठन से जुड़े मामलों पर जवाबदेही तय कर रहे हैं और इस पर विचार कर रहे हैं कि चुनाव की तैयारी अभी से कैसे की जाए।'' पार्टी के कुछ नेताओं की हालिया टिप्पणियों ने इस वर्ष के अंत में कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को एक बार फिर हवा दे दी है। राजनीतिक हलकों में, विशेषकर सत्तारूढ़ कांग्रेस में, इस वर्ष के अंत में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसमें सिद्दरामय्या और शिवकुमार के बीच सत्ता-साझाकरण समझौते का हवाला दिया गया है। पार्टी आलाकमान के कड़े निर्देशों के बाद ऐसी चर्चाएं कुछ समय के लिए थम गयी थीं। मई 2023 में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्दरामय्या और शिवकुमार के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी और कांग्रेस शिवकुमार को मनाने में कामयाब रही तथा उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया। उस समय कुछ खबरें थीं कि क्रमिक मुख्यमंत्री फॉर्मूले के आधार पर समझौता हुआ है, जिसके अनुसार शिवकुमार ढाई साल बाद मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन पार्टी द्वारा इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

मैं पांच साल तक कर्नाटक का मुख्यमंत्री रहूंगा : सिद्दरामय्या

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चिक्कबल्लापुर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने बुधवार को कहा कि वह पांच साल के पूरे कार्यकाल के दौरान पद पर बने रहेंगे। सिद्दरामय्या ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और पार्टी की सरकार पांच साल तक चट्टान की तरह ''मजबूत'' रहेगी। पत्रकारों ने सिद्दरामय्या से सवाल किया कि क्या वह पांच साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे जिसके जवाब में वरिष्ठ नेता ने कहा, ''हां, मैं रहूंगा। आपको इसमें संदेह क्यों है?'' राजनीतिक हलकों में, विशेषकर सत्तारूढ़ कांग्रेस में, सिद्दरामय्या और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के बीच सत्ता-साझाकरण समझौते का हवाला देते हुए इस वर्ष के अंत में मुख्यमंत्री बदले जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। शिवकुमार ने हालांकि मंगलवार को कहा था कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन पर कोई चर्चा नहीं हो रही और उन्होंने राज्य में मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या एवं पार्टी की सरकार के हाथ मजबूत करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री को बदले जाने संबंधी भाजपा (भारतीय जनता पार्टी)

और जनता दल-एस (जद-एस) के नेताओं के दावे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सिद्दरामय्या ने कहा, ''क्या वे हमारे आलाकमान हैं?''

उन्होंने कहा, ''आर अशोक (विधानसभा में विपक्ष के नेता) भाजपा के नेता हैं। विजयेंद्र येडीयुरप्पा(भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष) भाजपा के नेता हैं। चलवाडी नारायणस्वामी (विधान परिषद में विपक्ष के नेता) भाजपा के नेता हैं। अगर वे ऐसी बातें करते हैं तो क्या आप लिखेंगे? आपको इसकी पुष्टि करनी चाहिए या नहीं?'' भाजपा पर सरकार की स्थिरता के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए सिद्दरामय्या ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और सरकार पांच साल तक चट्टान की तरह ''मजबूत'' रहेगी। उन्होंने कहा, ''भाजपा पर कोई विश्वास नहीं करता। वे केवल झूठ बोलते हैं। वे झूठ बोलने में माहिर हैं। वे सच बोलना नहीं जानते। ...(कांग्रेस में) हम सब एक साथ हैं। जैसा कि मैंने हाल में मैसुरु में कहा था, हम पांच साल तक सत्ता में रहेंगे। हमारी सरकार चट्टान की तरह मजबूत रहेगी। भाजपा के लोग दिवास्वप्न देख रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ''वे (भाजपा) करीब चार साल तक सत्ता में रहे और मुख्यमंत्री के तौर पर एच डी कुमारस्वामी के कार्यकाल में जद (एस) के साथ करीब एक साल तक गठबंधन सरकार में रहे।

कन्नड़-हिंदी कोश निर्माण की पंचम कार्यशाला संपन्न

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मैसूरु। केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के मैसूर केंद्र पर 27 जून से 2 जुलाई तक तक आयोजित कन्नड़-हिंदी पर्याय कोश निर्माण हेतु पंचम कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कोश के अंतर्गत कन्नड-हिंदी के किया गया। इस छह दिवसीय कार्यशाला में कुल छह विषय विशेषज्ञों प्रो. टी. आर भट्ट, कार्यशाला संयोजक; प्रो. संदीप रणभिरकर, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय; प्रो. श्रीधर हेगड़े, हिंदी विभाग, मंगलूरु विश्वविद्यालय; प्रो. परमेश्वर हेगडे, मैसूर; डॉ. आशा भाद्री, हुब्बल्ली धारवाड़; डॉ. लता कुलकर्णी, धारवाड़ ने योगदान दिया। कार्यशाला के संयोजक प्रो. भट्ट ने बताया कि कार्यशाला के दौरान अब तक कुल 6800 कन्नड़-हिंदी समान शब्दों, 700 लोकोक्तियों एवं 500 मुहावरों को संग्रहित किया गया। जो अपने आप में एक तरह का यूनिक कार्य है। इस कार्यशाला में कोश निर्माण को अंतिम रूप दिया गया और इसे टंकित कर जल्द ही लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा।

यह कोश एक अध्येता कोश है जो हिंदी माध्यम से कन्नड़ सीखने वाले शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस कार्यशाला का पूरा व्यय केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा किया गया है तथा इसका आयोजन केंद्रीय हिंदी संस्थान के मैसूर केंद्र पर किया गया। कार्यशाला आयोजन संबंधी समस्त कार्य क्षेत्रीय निदेशक डॉ. रणजीत भारती एवं केंद्र के कर्मियों द्वारा किया गया।

एचसीजी ने अपने केंद्र में अनुचित परीक्षण किए जाने के आरोपों को खारिज किया

बेंगलूरु। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के जुड़ी कंपनी हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड' (एचसीजी) ने अनुचित परीक्षण किए जाने के आरोपों को बुधवार को खारिज करते हुए कहा कि वह अत्यंत पारदर्शिता के साथ और रोगियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अपनी नैतिकता समिति द्वारा स्वीकृत बड़ी संख्या में क्लीनिकल परीक्षण सफलतापूर्वक कर रही है। इस कंपनी का मुख्यालय बेंगलूरु में है।

एचसीजी की संस्थागत नैतिकता समिति के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति पी. कृष्ण भट (सेवानिवृत्त) ने कंपनी पर अनुचित परीक्षण करने के आरोप लगाए थे जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) को पत्र लिखकर एचसीजी में कथित अनुचित क्लीनिकल ड्रग्स परीक्षण किए जाने के मामले की जांच की मांग की थी। कंपनी ने हालांकि आश्वासन दिया कि वह डीसीजीआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) सहित नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करती है। उसने कहा, ''हमने भारत और अफ्रीका में कैंसर देखभाल में अग्रणी एचसीजी के बारे में कुछ असत्यापित जानकारी देखी है। हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम डीसीजीआई और आईसीएमआर सहित नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करते हैं।''

बेंगलूरु भगदड़ मामला : बीसीसीआई लोकपाल ने आरसीबी, केएससीए को लिखित में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु (आरसीबी) की मुश्किल तब और बढ़ गई जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के लोकपाल-सह-आचरण अधिकारी न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण मिश्रा ने फ्रेंचाइजी और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) को बेंगलूरु में टीम के विजय समारोह के दौरान घोर लापरवाही के बारे में लिखित में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। आईपीएस अधिकारी विकास कुमार द्वारा दर्ज की गई आधिकारिक शिकायत के बाद लोकपाल ने आरसीबी और केएससीए को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। पीटीआई के पास लोकपाल के निर्देश की एक प्रति है। शिकायतकर्ता ने लोकपाल से यह भी आग्रह किया है कि जब तक त्रासदी की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक मौजूदा मालिकों को फ्रेंचाइजी को बेचने से रोका जाए। न्यायमूर्ति मिश्रा ने अपने निर्देश में लिखा, ''घटना की गंभीरता को देखते हुए यह उचित माना जाता है कि कर्नाटक (राज्य) क्रिकेट संघ, साथ ही संबंधित फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को शिकायत पर अपना लिखित जवाब देने के लिए कहा जाए।'' उन्होंने कहा, ''यह शिकायत चार जून 2025 को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ के संबंध में दर्ज की गई है। शिकायत में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर फ्रेंचाइजी द्वारा घोर लापरवाही और सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि जवाबदेही तय की जानी चाहिए। आरसीबी फ्रेंचाइजी को निलंबित करने और इसे बेचने को लेकर चल रही बातचीत को अमान्य करने की प्रार्थना की गई है।''

न्यायमूर्ति मिश्रा ने अपने निर्देश में यह भी उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता विकास कुमार को प्रतिवादियों को जवाबी हलफनामा देने के लिए 10 दिन का समय मिलेगा। उन्होंने कहा, ''केएससीए और आरसीबी को शिकायत पर अपने-अपने लिखित जवाब चार सप्ताह के भीतर दाखिल करने चाहिए, साथ ही शिकायतकर्ता को भी प्रति देनी चाहिए। कारण बताएं कि नियमों में निर्दिष्ट और मांगी गई राहत क्यों नहीं दी जाए। यदि जरूरी हो तो प्रतिवादी को प्रति के साथ 10 दिनों के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जा सकता है।'' आरसीबी से लिखित स्पष्टीकरण मांगने के संभावित कारणों में से एक यह हो सकता है कि इस तरह की अटकलें हैं कि फ्रेंचाइजी को बेचने पर विचार चल रहा है जिससे मौजूदा मालिक कथित तौर पर हाल की त्रासदी से खुद को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कहा गया, आशंका व्यक्त की गई है कि फ्रेंचाइजी खुद को जवाबदेही से दूर करने और संभावित नतीजों से बचने के लिए स्वामित्व को बेचने का प्रयास कर सकती है। इस बीच यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए। हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने भी आरसीबी को भारी भीड़ के लिए जिम्मेदार माना जिसके कारण महिलाओं और बच्चों सहित 11 प्रशंसकों की मौत हो गई। न्यायाधिकरण ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास कुमार के खिलाफ कर्नाटक सरकार के निलंबन आदेश को भी रद्द कर दिया था जिन्हें भगदड़ के बाद कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। विकास कुमार ने बाद में कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती दी थी।

सिद्दरामय्या ने रेल किराये में वृद्धि को तुरंत वापस लिए जाने की मांग की

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या ने रेल के किराये में वृद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए इस फैसले को तुरंत वापस लिए जाने की मांग की है। रेल मंत्रालय ने सोमवार को एक आधिकारिक परिपत्र जारी कर एक जुलाई से मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में गैर-वातानुकूलित श्रेणी के किराए में एक पैसा प्रति किलोमीटर और सभी वातानुकूलित श्रेणी में दो पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि की घोषणा की। सिद्दरामय्या ने मंगलवार को 'एक्स' पर कहा, ''रेल किराए में बढ़ोतरी। इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? दिहाड़ी मजदूर, छात्र, छोटे व्यापारी और आम आदमी बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ''जब हमने अपने किसानों की मदद के लिए दूध के दाम बढ़ाए तो कर्नाटक भाजपा ने सड़कों पर शोर मचाया और इसे जनविरोधी बताया लेकिन अब जब भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने रेल किराया बढ़ाया तो इस पर चुप्पी छा गई। क्यों? क्योंकि इस बढ़ोतरी से किसानों या गरीबों को कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि इससे भाजपा सरकार को अपना खजाना भरने में मदद मिलती है।'' उन्होंने कहा कि जब कर्नाटक में आठ साल बाद मेट्रो का किराया बढ़ाया गया तो भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराना शुरू कर दिया जबकि उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया कि किराया वृद्धि का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा गठित किराया निर्धारण समिति द्वारा लिया गया था।

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बेंगलूरु ग्रामीण जिले का नाम बदलकर बेंगलूरु उत्तर किया

चिक्कबल्लापुरा। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बुधवार को बेंगलूरु ग्रामीण जिले का नाम बदलकर बेंगलूरु उत्तर' करने को मंजूरी दे दी। नंदी हिल्स पर मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बेंगलूरु ग्रामीण में वर्तमान में चार तालुका होसकोटे, देवनहल्ली, दोड्डबल्लापुर और नेलमंगला शामिल हैं। बैठक के बाद सिद्दरामय्या ने संवाददाताओं से कहा, 'हमने बेंगलूरु ग्रामीण जिले का नाम बदलकर बेंगलूरु उत्तर कर दिया है।' बता दें कि वर्ष 1986 में बेंगलूरु को बेंगलूरु शहरी और बेंगलूरु ग्रामीण में विभाजित किया गया था। वर्ष 2007 में बेंगलूरु ग्रामीण से रामनगर जिला बनाया गया था।

सुविचार

राधा को खोजने कृष्ण कहीं नहीं गए, क्योंकि प्रेम रास्ता खुद बना लेता है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

डिजिटल इंडिया: एक क्रांतिकारी पहल

पिछले एक दशक में 'डिजिटल इंडिया' पहल ने देशवासियों के जीवन को आसान बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत, जो अत्यंत विविधतापूर्ण देश है, में इस पहल को बहुत संदेह की दृष्टि से देखा गया था। कुछ 'बुद्धिजीवी' तो यह दावा करते थे कि लोगों के पास अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए संसाधन नहीं हैं, लिहाजा वे डिजिटल तौर-तरीकों से दूर ही रहेंगे। हालांकि देशवासियों ने उन्हें पूरी तरह गलत साबित कर दिया। आज डिजिटल सेवाओं का बहुत विस्तार हो चुका है। एक दशक पहले लोगों को अपनी कई जरूरतों के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। 'डिजिटल इंडिया' ने उनकी जटिलताओं को दूर किया है। याद करें, वर्ष 2014 और उससे पहले बिजली का बिल चुकाने के लिए कितनी लंबी कतारें लगती थीं? बैंक से संबंधित किसी काम के लिए जाते थे तो कितना समय लगता था? रसोई गैस सिलेंडर लेने जाते तो कितने समय बाद बारी आती थी? सिनेमा, बस और ट्रेन की टिकटें लेने का अनुभव कैसा होता था? कई बार तो उन कतारों में धक्का-मुक्की, बहस आदि की वजह से झगड़े तक हो जाते थे। अब डिजिटल इंडिया' की वजह से विभिन्न सेवाएं तथा सुविधाएं मोबाइल फोन पर कुछ ही सेकंडों में आसानी से मिल जाती हैं। यह तो एक शुरुआत है। देश में डिजिटलीकरण का जिस तरह विस्तार होता जा रहा है, वह अगले दशक में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। उस समय किशोरों और नौजवानों को आश्चर्य होगा कि उनके माता-पिता और घर के बड़े सदस्यों को कभी कतारों में लगना होता था,

दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे! मोदी सरकार को इस बात का श्रेय मिलना चाहिए, जिसने तमाम आलोचनाओं के बावजूद डिजिटलीकरण के जरिए सेवाओं तथा सुविधाओं का सरलीकरण जारी रखा। 'डिजिटल इंडिया' पहल की वजह से समय, संसाधन और ऊर्जा की बचत हुई है। पहले, बैंकिंग सेवाएं एक खास वर्ग तक सीमित थीं। ग्रामीण आबादी इससे वंचित थी। खाता खुलवाने से लेकर छोटी-छोटी सेवाओं के लिए लंबी कागजी प्रक्रिया होती थी। उस व्यवस्था ने कई बिचौलियों को जन्म दिया, जो जरूरतमंद लोगों से धन ऐंठते थे। सरकारें कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाती थीं, उनका बहुत बड़ा हिस्सा बिचौलिए और भ्रष्टाचारी खा जाते थे। एक पूर्व प्रधानमंत्री ने तो स्वीकार किया था कि सरकार 100 पैसे भेजती थी तो उसमें से 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। अगर आज सरकार दूर-दराज के इलाके में रहने वाले किसी किसान के खाते में रुपए भेजती है तो उसे पूरी रकम मिलती है। एक पैसा भी कम नहीं होता। क्या यह देश की उपलब्धि नहीं है? क्या इससे भ्रष्टाचारियों पर लगाम नहीं लगी है? वास्तव में 'डिजिटल इंडिया' पहल किसी जन-आंदोलन से कम नहीं है। इसने परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। इसने मोबाइल फोन को कई जरूरतों का एक ठिकाना बना दिया है। भारत ने सबसे बड़ा कीर्तिमान तो डिजिटल लेनदेन के क्षेत्र में बनाया है। यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म की सफलता से अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान जैसे देश हैरान हैं। एक वर्ष में 100 अरब से ज्यादा लेनदेन को संभालना कोई मामूली बात नहीं है। आधे 'रियल टाइम' डिजिटल लेनदेन का भारत में होना हमारे लिए गर्व का विषय है। जो देश तकनीक और संसाधनों के मामले में बहुत संपन्न माने जाते हैं, वे हमारे आस-पास भी नहीं हैं। आधार, डिजिलॉकर, कोविन और फास्टैग को दुनियाभर से सराहना मिल रही है। इंटरनेट ने हुनरमंद लोगों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। आज वे गांवों में रहकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। 'डिजिटल इंडिया' देशवासियों के सपनों को हकीकत में बदलने का संकल्प साबित हो रहा है।

ट्वीटर टॉक

कुशल संगठनकर्ता, भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान के माननीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद श्री मदन राठौड़ जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! आपके ऊर्जावान नेतृत्व में प्रदेश भाजपा सफ़लता की नित नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रही है।

-भजनलाल शर्मा

आज सिविल लाइंस स्थित कार्यालय पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों एवं विद्याधर नगर विधानसभा से पधारे पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

-दीया कुमारी

बांसवाड़ा की यह खबर राजस्थान की कानून एवं चिकित्सा व्यवस्था दोनों की पोल खोलने के लिए काफी है। एक तरफ आरोपी जेल से जमानत पर बाहर आकर पुनः खुले आम शिक्षिका की तलवार से हत्या कर देता है क्योंकि उसके मन में पुलिस का कोई खौफ नहीं है।

-अशोक गहलोत

प्रेरक प्रसंग

शांति का योद्धा

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिक डेसमंड डॉस ने एक असाधारण निर्णय लिया वह युद्ध में जाएगा, लेकिन बिना हथियार उठाए। उसका विश्वास था कि जीवन देना उसका धर्म है, न कि लेना। साथियों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे डरपोक कहा और अपमानित किया, लेकिन वह अडिग रहा। वह सैन्य डॉक्टर बना और जापान के भयंकर ओकिनावा युद्ध में तैनात हुआ। एक दिन जब गोलाबारी के बीच सभी सैनिक पीछे हट चुके थे, डॉस अकेला युद्धभूमि में रुका रहा और एक-एक कर 75 घायल सैनिकों को अपने कंधे पर उठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। उसके पास न बंदूक थी, न ढाल सिर्फ संकल्प और मानवता का साहस। अद्वितीय योगदान के लिए डेसमंड डॉस को अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मान 'मेडल ऑफ ऑनर' दिया गया। यह सम्मान पाने वाला वह पहला व्यक्ति था जिसने युद्ध में हथियार नहीं उठाए।

सामयिक

सहयोग की शक्ति और सामाजिक समरसता का उत्सव

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) ने इस पहल का गर्मजोशी से स्वागत किया है। आईसीए के अध्यक्ष एरियल ग्वार्को ने इस घोषणा को संगठन के सतत विकास के लिए चल रहे प्रयासों के साथ संरेखित करने पर प्रकाश डाला। इस घोषणा से वैश्विक स्तर पर समानतापूर्ण और लचीली अर्थव्यवस्था बनाने में सहकारी समितियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है, खासकर जलवायु परिवर्तन और आर्थिक असमानता जैसी वैश्विक चुनौतियों के सामने। सहकारिता पर ध्यान केंद्रित करके, संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य टिकाऊ, समुदाय-केंद्रित समाधान प्रदान करने में मॉडल की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करना है।

ललित गर्ग

मोबाइल : 9811051133

हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। यह दिन सहकारी संस्थाओं की उपलब्धियों को रेखांकित करने और उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान को सम्मानित करने का अवसर होता है। सहकारिता एक ऐसा आंदोलन है जो एकता में शक्ति' की भावना को मजबूत करता है और लोकतांत्रिक, समावेशी और न्यायसंगत आदर्श समाज के निर्माण में सहायक बनता है। सहयोग की शक्ति और सामाजिक समरसता के इस उत्सव का 2025 की थीम है सहकारिता: एक बेहतर दुनिया के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान लाना।' यह थीम पर्यावरण-संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, और सामाजिक समावेशन जैसे विषयों को सहयोग के माध्यम से हल करने की प्रेरणा देती है। आज के समय में जब आर्थिक विषमता और सामाजिक असंतुलन बढ़ रहा है, सहकारिता एक वैकल्पिक और मानवीय मॉडल प्रस्तुत करती है। यह न केवल आर्थिक विकास की राह दिखाती है, बल्कि सामाजिक विश्वास, सह-अस्तित्व और भाईचारे को भी बढ़ावा देती है।

इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त यह 29वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस और 101वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस होगा। यह सहकारी आंदोलन का एक वार्षिक उत्सव है जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन द्वारा 1923 से जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस उत्सव का उद्देश्य सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन के पूरक लक्ष्यों और उद्देश्यों को उजागर करना, संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबोधित प्रमुख समस्याओं के समाधान में आंदोलन के योगदान को रेखांकित और विस्तारित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया है। यह घोषणा 2012 में पहले सफल आयोजन के बाद की गई है और वैश्विक स्तर पर सतत विकास को बढ़ावा देने में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देती है। दुनिया भर की सहकारी समितियां दिखाएंगी कि कैसे वे एकजुटता और लचीलेपन के साथ युद्ध, महामारी एवं प्राकृतिक आपदा संकट का सामना कर रही हैं और समुदायों को जन-केंद्रित और पर्यावरण की दृष्टि से न्यायसंगत पुनर्प्राप्ति की पेशकश कर रही हैं।

सहकारिता दिवस इस बात का प्रचार करने का अवसर है कि किस प्रकार मानव-केन्द्रित व्यवसाय मॉडल, जो स्वयं-सहायता और एकजुटता के सहकारी मूल्यों तथा सामाजिक उत्तरदायित्व और समुदाय के प्रति चिंता के नैतिक मूल्यों द्वारा समर्थित है, असमानता को कम कर सकता है, साझा समृद्धि का सृजन कर सकता है। सहकारी समितियां, जो आर्थिक सफलता को सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ संतुलित करने की अपनी अनूठी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, उन्हें सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव सदस्य देशों को सहकारी समितियों के लिए एक सहायक कानूनी और नीतिगत माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें कृषि, वित्त और खुदरा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनके महत्व पर जोर दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) ने इस पहल का गर्मजोशी से स्वागत किया है। आईसीए के अध्यक्ष एरियल ग्वार्को ने इस घोषणा को संगठन के सतत विकास के लिए चल रहे प्रयासों के साथ संरेखित करने पर प्रकाश डाला। इस घोषणा से वैश्विक स्तर पर समानतापूर्ण और लचीली अर्थव्यवस्था बनाने में सहकारी समितियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है, खासकर जलवायु परिवर्तन और आर्थिक असमानता जैसी वैश्विक चुनौतियों के सामने। सहकारिता पर ध्यान केंद्रित करके, संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य टिकाऊ, समुदाय-केंद्रित समाधान प्रदान करने में मॉडल की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करना है।

सहकारिता, जिसे अंग्रेजी में कोआपरेटिव कहते हैं, एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग स्वेच्छा से मिलकर काम करते हैं ताकि अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यह एक लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित व्यवसाय है जहां सदस्य ही मालिक होते हैं और व्यवसाय का संचालन और लाभ का वितरण भी सदस्यों के बीच ही होता है। सहकारिता का अर्थ है, 'मिलजुल कर काम करना' या आपस में सहयोग करना'। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग स्वेच्छा से एक साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि वे अपने सामान्य आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें. सहकारिता का मुख्य उद्देश्य आपसी सहयोग, समानता और सामूहिक हित को बढ़ावा देना है। इसका मूल मंत्र है सभी के लिए एक, और एक सभी के लिए।'

भारत में सहकारिता की भावना एवं विचारधारा आजादी से पहले से जन-जन में रची-बसी है। भारत की जनता के स्वभाव में सहकारिता घुली मिली है, ये कोई उधार लिया विचार नहीं है। सहकारिता भारत के संस्कार में है। भारत में सहकारिता आंदोलन कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। सहकारिता की जड़े 1904 के सहकारी ऋण समितियां अधिनियम से जुड़ी हैं। स्वतंत्रता के बाद यह आंदोलन और भी सशक्त हुआ। चाहे अमूल जैसी डेयरी सहकारी संस्थाएं हों या सहकारी बैंकों और किसान समितियां, उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जब सहकारिता आंदोलन की सबसे अधिक जरूरत थी, तब यशस्वी एवं दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सहिकारिता मंत्रालय का गठन करके सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता को नये आयाम दिये हैं। उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से करोड़ों किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। सभी राज्यों के सहकारिता मंत्री अपने-अपने राज्यों में कृषि मंत्रियों के साथ समन्वय कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि आम लोगों के साथ-साथ धरती माता का स्वास्थ्य भी बेहतर हो सके।

गरीब कल्याण और गरीब उत्थान, बिना सहकारिता के सोचा नहीं जा सकता। नरेन्द्र मोदी के मन की इच्छा है कि छोटे से छोटे व्यक्ति को विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाना, सहकारिता की प्रक्रिया से हर घर को समृद्ध बनाना और हर परिवार की समृद्धि से देश को समृद्ध बनाना, यही सहकार से समृद्धि का मंत्र है। देश पर जब-जब कोई विपदा आई है, सहकारिता आंदोलनों ने देश को बाहर निकाला है। कॉपरेटिव बैंक बिना मुनाफे की चिंता किए लोगों के लिए काम करते हैं क्योंकि, भारत के संस्कारों में सहकारिता है। आज देश में लगभग 91 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहां छोटी-बड़ी कोई न कोई सहकारी संस्था काम करती है। सहकारिता गरीबों और पिछड़ों के विकास के लिए है। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम-(एनसीडीसी) और सहकारिता मंत्रालय जैसे संस्थान इस क्षेत्र को संगठित और सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं। भारत की सहकारिता सोच एवं मोदी सरकार की प्रतिबद्धताएं दुनिया के लिये एक प्रेरक मॉडल है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस केवल एक दिवस नहीं, बल्कि एक विचारधारा है, एक ऐसा आंदोलन जो समाज को जोड़ने, ऊपर उठाने, संतुलित विकास और ग्रामीण जीवन को टिकाऊ बनाने की क्षमता रखता है। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि यदि हम साथ मिलकर कार्य करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। सहयोग ही सशक्तिकरण की कुंजी है।

नजरिया

आतंकवाद पर भारत को वैश्विक मौन स्वीकार्य नहीं

योगेश कुमार गोयल

मोबाइल : 9416740584.

चीन के किंगदाओ में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की रक्षा मंत्रियों की बैठक इस बार भारत की आक्रामक और स्पष्ट कूटनीतिक रणनीति की स्पष्ट साक्षी बनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से जब यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि उसमें आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया गया है तो यह भारत का केवल एक औपचारिक विरोध नहीं था बल्कि भारत की सुरक्षा प्राथमिकताओं और कूटनीतिक दृढ़ता का स्पष्ट संकेत था। इस विरोध के जरिये उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि भारत अब केवल प्रतीकात्मक भाषणों और कूटनीतिक शिष्टाचारों से आगे बढ़ चुका है। भारत का संदेश दृढ़ है कि आतंकवाद को सामान्य नहीं माना जा सकता। भारत के इस फैसले को चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। भारत का यह कदम एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों पर दोहरे मापदंडों के खिलाफ खासकर उन देशों के लिए एक चेतावनी है, जो आतंकवाद को अपने रणनीतिक हितों के लिए एक औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भारत ने साफ कर दिया कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस' की नीति केवल शब्दों तक सीमित नहीं है बल्कि उसके व्यवहार में भी प्रतिबिंबित होती है। भारत का यह कदम पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग करने की रणनीति का हिस्सा तो है ही, चीन को भी यह स्पष्ट संदेश है कि भारत अपने सुरक्षा हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा।

एससीओ की बैठक में राजनाथ सिंह द्वारा की गई टिप्पणी कि 'आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है' और 'जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं या उसे पनाह देते हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए', सीधे तौर पर पाकिस्तान की ओर संकेत था, हालांकि उन्होंने उसका नाम नहीं लिया। दक्षिण एशिया पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों के कारण ही दशकों से अस्थिरता और हिंसा से जूझ रहा है और अब भारत इस खतरे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और मुखरता से उजागर कर रहा है। भारत की इस बार की विशेष आपत्ति पहलगाम हमले को लेकर थी। यह हमला लश्कर-ए-तैयबा की सहायक इकाई टीआरएफ' (द रेजिस्टेंस फ्रंट) द्वारा किया गया था, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। यह हाल के वर्षों का सबसे भीषण आतंकी हमला था। भारत ने एससीओ के मसौदा दस्तावेज में इस हमले का उल्लेख नहीं किए जाने को गंभीर चूक नहीं बल्कि एक सोची-समझी रणनीति माना, जिसके पीछे पाकिस्तान को बचाने की कोशिश साफ दिखती है। भारत का यह रुख अचानक नहीं बना बल्कि यह उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें भारत हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग की बात करता रहा है और दोहरे मानदंडों को उजागर करता रहा है। इससे पहले भी भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) में शामिल होने से इन्कार कर दिया था क्योंकि उसमें चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) को शामिल किया गया था, जो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। एससीओ की स्थापना 2001 में चीन, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाखस्तान के साथ हुई थी। हालांकि इसकी जड़ें शंघाई फाइव' से जुड़ी हैं, जो 1996 में चीन, रूस तथा तीन मध्य एशियाई गणराज्यों द्वारा सीमा सुरक्षा विश्वास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक समूह है। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने। इस संगठन का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संवाद था परंतु बीते वर्षों में यह मंच धीरे-धीरे चीन और पाकिस्तान के राजनीतिक एजेंडे का उपकरण बनता गया है। आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर इस संगठन की चुप्पी उसकी प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह लगा रही है। इस बार के संयुक्त घोषणापत्र में बलूचिस्तान में कथित आतंकी घटनाओं का उल्लेख तो किया गया लेकिन पहलगाम जैसे जघन्य हमले को अनदेखा किया गया। भारत ने इसे पाकिस्तान के आरोपों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वैधता देने की साजिश बताया। बलूचिस्तान में विद्रोही गतिविधियां वहां के लोगों की आत्मनिर्णय की मांग से जुड़ी हैं, जिन्हें पाकिस्तान भारत-प्रायोजित आतंकवाद कहकर गुमराह करने की कोशिश करता है। चीन, जो सीपीईसी के माध्यम से बलूचिस्तान में भारी निवेश कर रहा है, पाकिस्तान के इन दावों का समर्थन करता रहा है। यही कारण है कि भारत को इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट इन्कार करना पड़ा।

यह पहली बार नहीं है, जब भारत ने एससीओ में ऐसा सख्त रुख अपनाया हो। बिश्केक (2019) और अस्ताना (2024) में भी भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हालांकि उस समय भारत ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे परंतु इस बार की परिस्थिति अलग थी। इस बार एक ऐसा हमला हुआ था, जिसमें निर्दोष नागरिकों की जान गई और उसे एससीओ की बैठक में पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया। भारत का यह कड़ा रुख केवल एससीओ तक सीमित नहीं है। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकी शिविरों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। भारत का यह स्पष्ट संदेश था कि अब वह आतंकवाद के केंद्रों को उनकी सीमा में घुसकर खत्म करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। यह संदेश भी चीन और पाकिस्तान के लिए था कि भारत अब केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में भी आक्रामक कूटनीति अपना रहा है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान भी स्पष्ट किया कि विश्वास-निर्माण तभी संभव है, जब चीन एलएसी पर अतिक्रमण की अपनी नीतियों को छोड़े और भारत की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से ले। दोनों पक्षों ने सैन्य हॉटलाइन बहाल करने पर विचार किया लेकिन भारत ने यह भी जता दिया कि यह केवल दिखावटी बातचीत नहीं होनी चाहिए। भारत के इस सख्त रुख का एक और आयाम है, बिना उलझाव के संरेखण की नीति। भारत न किसी गुट का हिस्सा बनना चाहता है, न किसी के हितों का औजार। वह केवल अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर बहुपक्षीय मंचों पर भाग लेता है और किसी भी ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करता, जो उसकी संप्रभुता, सुरक्षा या वैचारिक सिद्धांतों से टकराव रखता हो। यह नीति भारत को एक स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से परिपक्व राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करती है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत वैश्विक समर्थन जुटाने की दिशा में भी काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति में भारत लगातार मांग करता रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और टीआरएफ जैसे संगठनों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। चीन ने कई बार तकनीकी आपत्ति लगाकर इन प्रयासों को विफल किया है लेकिन भारत ने अपने प्रयासों को कभी धीमा नहीं किया। एससीओ की इस बार की बैठक का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत अब सामूहिक सहमति' की कीमत पर अपने राष्ट्रीय हितों' की बलि नहीं चढ़ाएगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों को नाम लेकर नहीं लताड़ा जाएगा, तब तक कोई संयुक्त घोषणापत्र केवल कागज का एक टुकड़ा ही रहेगा। भारत के लिए यह रुख न केवल सम्मान का विषय है बल्कि वैश्विक मंचों पर उसकी विश्वसनीयता और नेतृत्व क्षमता को भी बढ़ाता है। आज भारत को वैश्विक मंचों पर सुना जा रहा है क्योंकि वह केवल बातें नहीं करता बल्कि अपने रुख पर अडिग भी रहता है। बहरहाल, अंततः, भारत ने एससीओ के मंच से जो सख्त संदेश दिया है, वह केवल पाकिस्तान या चीन के लिए नहीं बल्कि उन सभी देशों के लिए भी है, जो आतंकवाद पर मौन साधे रहते हैं या अपने आर्थिक, कूटनीतिक हितों के कारण उसे नजरअंदाज करते हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद अब केवल एक देश की समस्या नहीं है, यह वैश्विक मानवता के लिए खतरा है और इसके खिलाफ कूटनीतिक मंचों से लेकर वास्तविक जमीनी कार्रवाई तक निर्णायक लड़ाई लड़ी जानी चाहिए।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**, (*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।- दक्षिण भारत राष्ट्रमत

केनरा बैंक ने वैश्विक कारोबार 25 लाख करोड़ पार

120वां स्थापना दिवस मनाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक केनरा बैंक अपना 120 वां स्थापना दिवस मना रहा है, जिसमें ग्राहक-केंद्रित नवाचार और समावेशी बैंकिंग पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है। 1906 में स्थापित, बैंक एक मजबूत विरासत और विश्वास के साथ भारत के बैंकिंग क्षेत्र के अग्रदूतों में से एक के रूप में उभरा है। केनरा बैंक ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सभी बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता को समाप्त करने की घोषणा की है। यह महत्वपूर्ण कदम यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक ग्राहक, चाहे उनकी वित्तीय पृष्ठभूमि कुछ भी हो, न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने के बोझ के बिना बचत खाते तक पहुँच सकता है और उसे बनाए रख सकता है। अपनी महत्वपूर्ण वित्तीय क्षमता का प्रदर्शन करते हुए, केनरा बैंक का वैश्विक कारोबार 725 लाख करोड़ से अधिक है। केनरा बैंक द्वारा राष्ट्र को दी गई सेवा के 120 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर, केनरा बैंक के एमडी और सीईओ सत्यनारायण राजू ने कहा, मेरा दिल असीम कृतज्ञता से भर गया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि 12 करोड़ से अधिक ग्राहकों के अटूट विश्वास, हमारे हितधारकों की दृढ़ प्रतिबद्धता और पूरे देश में हमारे शुभचिंतकों के अटूट समर्थन का प्रमाण है। 1 जुलाई, 1906 को हमारी विनम्र शुरुआत से लेकर आज तक, देश भर में 9,800 से अधिक शाखाओं के साथ मजबूती से खड़े रहने तक, हमारी यात्रा को विश्वास, एकजुटता और परिवर्तन के मूल मूल्यों द्वारा परिभाषित किया गया है। ये मूल्य हमें प्रेरित करते रहते हैं क्योंकि हम उद्देश्य, नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ आगे बढ़ते हैं।

उन्होंने आगे कहा, इस ऐतिहासिक अवसर पर, मैं अपने प्रत्येक ग्राहक, हितधारक और शुभचिंतकों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और देश की सेवा ईमानदारी, समावेशिता और उत्कृष्टता के साथ करने की अपनी प्रतिज्ञा की पुष्टि करता हूँ। साथ मिलकर हमने बहुत कुछ हासिल किया है। और साथ मिलकर हम और भी बहुत कुछ हासिल करेंगे।

केनरा बैंक अपनी 120वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसलिए यह अभिनव, समावेशी और ग्राहक-अनुकूल बैंकिंग समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखता है। कैनरा ट्रूएज सुइट सहित बैंक की नवीनतम पहल, संस्थागत ग्राहकों के लिए अनुरूप डिजिटल बैंकिंग और बीमा लाभ प्रदान करती है, जबकि कैनरा एस्पायर एक शून्य-शेष, युवा-केंद्रित बचत खाता प्रदान करता है जिसमें विशेष शैक्षिक और बीमा लाभ होते हैं, जो एक साथ हम कर सकते हैं के अपने दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।

केरल में अटका ब्रिटिश लड़ाकू विमान राज्य के पर्यटन को दे रहा बढ़ावा

तिरुवनंतपुरम/भाषा। पिछले महीने ब्रिटिश रॉयल नेवी एफ-35बी लाइटनिंग लड़ाकू विमान के तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन स्थिति में उतरने के बाद, केरल पर्यटन के लिए यह अप्रत्याशित रूप से एक उपहार बन गया है। यह विमान, ब्रिटेन के सबसे उन्नत 'स्टील्थ' बेड़े का हिस्सा है, जो अपनी मरम्मत का इंतजार कर रहा है।

हालांकि अब, पर्यटन का प्रचार करने के लिए इसकी तस्वीरों का उपयोग किया जा रहा है। केरल पर्यटन द्वारा अपने 'एक्स' हैंडल पर पोस्ट किया गया एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें इस लड़ाकू विमान को नारियल के पेड़ों और हरी-भरी पृष्ठभूमि के साथ दिखाया गया है। एक मजेदार शीर्षक में लिखा हुआ है, ''केरल एक अद्भुत जगह है, मैं इसे छोड़ कर नहीं जाना चाहता। निश्चित रूप से यहां आने को कहूंगा।'' इस उद्धरण को मजाकिया अंदाज में ''यूके एफ-35बी'' के लिए लिखा गया है। हालांकि, सोशल मीडिया पर चर्चा सिर्फ एक पोस्टर तक ही सीमित नहीं है। 'एक्स' पर व्यापक रूप से साझा की गई पोस्ट में, सुमोना चक्रवर्ती नाम के उपयोगकर्ता ने मजाकिया अंदाज में लिखा है, ''अब यह नारियल तेल के बिना चालू नहीं होगा।' केरल में भोजन बनाने में व्यापक रूप से नारियल तेल का इस्तेमाल किया जाता है। व्यक्ति ने अपना स्वयं का पोस्टर बनाया, जिसमें लड़ाकू विमान को सड़क किनारे चाय की दुकान के बाहर खड़ा दिखाया है-केले के चिप्स का आनंद ले रहा और शीर्षक में लिखा है, ''इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह अब जाने से इनकार कर रहा है।

शुभारंभ

बेंगलूरु के यलहंका क्षेत्र में बुधवार को भारत में त्वचा विशेषज्ञ-नेतृत्व वाले क्लीनिकों की सबसे भरोसेमंद श्रृंखला 'काया' ने 12वें क्लिनिक का उदघाटन कन्नड़ फिल्म स्टार सप्तमी गौड़ा ने किया। इस मौके पर काया के मार्केटिंग प्रमुख निशांत नैयर एवं कम्पनी के वरिष्ठजन उपस्थित थे।

आज विदेशों में भी लोग भारत के डिजिटल नेतृत्व के बारे में बातें करते हैं : डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी

आईएमसी ने बेंगलूरु में रोड शो किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) ने मंगलवार को बेंगलूरु में रोड शो निकाला। दूरसंचार विभाग (डीओटी) और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) द्वारा आयोजित 'आईएमसी 2025' ने महत्त्वपूर्ण लॉन्चपैड के रूप में बेंगलूरु पर ध्यान केंद्रित किया है, जो शहर के मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम और तकनीकी उन्नति में नेतृत्व को दर्शाता है। इस साल आईएमसी अपने प्रमुख एस्पायर कार्यक्रम के जरिए स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को सशक्त बनाने पर खास जोर दे रहा है, जो 500 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, लाइव पिचिंग और नेटवर्किंग के लिए निवेशकों, इनक्यूबेटर्स और ग्लोबल साझेदारों से जोड़ेगा।

आईएमसी 2025 रोड शो में संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, दूरसंचार विभाग (डीओटी) के सचिव डॉ. नीरज मित्तल, सीओएआई के अध्यक्ष अभिजीत किशोर ने विचार व्यक्त किए, जिससे इस आयोजन और भारत के डिजिटल नेतृत्व के लिए प्रेरणा मिली। डॉ. पेम्मासानी ने कहा, '40,000 अतिरिक्त ग्राम पंचायतों और 1.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए 18 बिलियन डॉलर का और निवेश कर रहे हैं।

'मेड फॉर इंडिया' से मेड बाय इंडिया' की ओर बदलाव आ रहा है। जापान, थाईलैंड और आसियान देशों में भी लोग भारत के डिजिटल नेतृत्व और आईएमसी जैसे आयोजनों के बारे में बातें करते हैं।'

कंगना ने की 'तन्वी द ग्रेट' के ट्रेलर की तारीफ, बोलीं- 'फिल्म का बेसब्री से इंतजार'

मुंबई/एजेन्सी

अनुपम खेर के निर्देशन में तैयार फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' का ट्रेलर सोमवार को जारी हो चुका है। फिल्म के ट्रेलर की एक्टर शाहरुख खान-अनिल कपूर ने तारीफ की और इसे शानदार बताया। मंगलवार को एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वह फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। कंगना ने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन पर ट्रेलर को पोस्ट कर फिल्म देखने की उत्सुकता जताई। उन्होंने लिखा, अनुपम खेर और 'तन्वी द ग्रेट' की पूरी टीम को बधाई। ट्रेलर बहुत पसंद आया, फिल्म का बेसब्री से इंतजार है।

शाहरुख खान ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, मेरे दोस्त अनुपम खेर, हमेशा से चांस लेते आए हैं, चाहे सवाल एक्टिंग-फिल्म मेकिंग हो या फिर लाइफ का, वह चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। 'तन्वी- द ग्रेट' का ट्रेलर शानदार है, फिल्म के लिए मेरी ढेरों शुभकामनाएं। अनिल कपूर ने 'तन्वी- द ग्रेट' का ट्रेलर शेयर किया और लिखा, कुछ कहानियां पर्दे से हटने के बाद भी हमसे जुड़ी रहती हैं, 'तन्वी- द ग्रेट' उनमें से एक बनने वाली है, अभी जाकर ट्रेलर देखो, यह दिल को छूने वाली कहानी है, जो अंदर से प्रेरित करती है। 'तन्वी- द ग्रेट' का ट्रेलर के साथ मेरी शुभकामनाएं।

30 जून को 'तन्वी द ग्रेट' के निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया। ट्रेलर में 'तन्वी' नाम की एक ऐसी लड़की की कहानी की झलक दिखाई गई, जो अपने मजबूत और दृढ़ निश्चय के कारण खास मुकाम पाती है। 'तन्वी द ग्रेट' का संगीत ऑस्कर विजेता एमएम कीरावानी ने तैयार किया है और अनुपम खेर स्टूडियोज और एनएफडीसी के साथ मिलकर बनाई गई है।

भारतनेट प्रोजेक्ट : आईटीआई लि. ने बीएसएनएल के साथ 1901 करोड़ का समझौता किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु/नई दिल्ली। प्रमुख दूरसंचार विनिर्माण कंपनी आईटीआई लिमिटेड ने हाल में भारतनेट फेज-3 प्रोजेक्ट के एनईआर-2 पैकेज-15 के लिए यूएसओएफ की ओर से बीएसएनएल के साथ परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अनुबंध का कुल मूल्य पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) और परिचालन व्यय (ओपेक्स) सहित 1901 करोड़ रुपए है। ऑर्डर मूल्य में 1168 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय, नवनिर्मित नेटवर्क के लिए 700.84 करोड़ रुपए परिचालन व्यय तथा मौजूदा नेटवर्क के रखरखाव के लिए 32.21 करोड़ रुपए परिचालन व्यय शामिल है। आईटीआई लि. ने हिमाचल प्रदेश में पैकेज संख्या 8 के लिए तथा पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पैकेज संख्या 9 के लिए बीएसएनएल के साथ 5055 करोड़ रुपए के समेकित ऑर्डर मूल्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही आईटीआई लि. ने बीएसएनएल के साथ तीन पैकेजों (8,9 और 15) के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे कुल ऑर्डर मूल्य 6956 करोड़ रुपए हो गया है। नवंबर 2024 में, आईटीआई लि. अपने कंसोर्टियम पार्टनर के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर राज्यों को शामिल करते हुए भारतनेट फेज-3 प्रोजेक्ट के पैकेज नं. 15 के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली (एल1) के रूप में उभरी थी।

भारतनेट फेज-3 प्रोजेक्ट को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 16 पैकेजों में विभाजित किया गया है। बीएसएनएल ने भारतनेट चरण-3 प्रोजेक्ट के मिडल माइल नेटवर्क के लिए डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट और मेंटिनेंस (डीबीओएम) मॉडल पर निविदाएं आमंत्रित की थीं।

आईटीआई लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजेश राय ने कहा, 'हम भारतनेट फेज-3 प्रोजेक्ट के एक और पैकेज के निष्पादन के लिए यूएसओएफ की ओर से बीएसएनएल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करके बहुत खुश हैं। यह वास्तव में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट है और मैं आईटीआई पर एक बार फिर से विश्वास जताने के लिए बीएसएनएल का आभारी हूं। मेरी टीम पूरी तरह तैयार है और हम अपने क्लाइंट की पूर्ण संतुष्टि के लिए इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे।'

मैं डरावनी फिल्मों की शौकीन नहीं हूं: काजोल

नई दिल्ली/भाषा। अभिनेत्री काजोल का कहना है कि वह डरावनी फिल्मों की प्रशंसक नहीं हैं और वह केवल व्यावसायिक कारणों से इस शैली में अपनी पहली फिल्म मां देखेंगी।

विशाल फुरिया निर्देशित मां काजोल के 30 साल से अधिक के करियर की पहली 'हॉरर' फिल्म है। यह फिल्म 2023 की फिल्म शैतान से मिलती-जुलती है, जिसमें उनके पति और अभिनेता अजय देवगन भी थे। अभिनेत्री (50) ने यहां 'पीटीआई-भाषा' को दिए साक्षात्कार में कहा, मैं डरावनी फिल्में नहीं देखती। मैंने कई बड़ी फिल्में देखी हैं। मैं डरावनी फिल्मों की बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूं। उन्होंने कहा, मैंने अभी तक 'मां' नहीं देखी है। केवल कुछ हिस्सों में मेरे पीछे बहुत सारी हरी स्क्रीन लगी हुई हैं ताकि मैं डर न जाऊं और कोई पृष्ठभूमि संगीत या ऐसा कुछ भी नहीं है। (लेकिन) पेशेवर कारणों से मुझे वास्तव में यह फिल्म देखनी है। एक अभिनेत्री के रूप में, काजोल ने शुरू में यह मान लिया था कि डरावनी फिल्म में काम करना किसी भी अन्य शैली से अलग नहीं होगा। उन्होंने कहा, यह एक बहुत ही दिलचस्प अनुभव था, वास्तव में, ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने पहले किया था।

मैंने यह मान लिया था कि डरावनी फिल्मों में काम करना किसी भी अन्य फिल्म में काम करने जैसा ही है और मैं पूरी तरह से गलत थी। उन्होंने कहा कि अभिनय के लिहाज से डरावनी फिल्में आम फिल्मों से पूरी तरह अलग होती हैं।

एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान घायल हुईं अदा शर्मा

मुंबई/एजेन्सी

फिल्म अभिनेत्री अदा शर्मा अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हो गईं। एक्शन-थ्रिलर फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी नाक पर गंभीर चोट लगी है। 'द केरल स्टोरी' फेम अदा ने बताया कि यह चोट एक एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान लगी। फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि अदा इस फिल्म में जोरदार एक्शन सीक्वेंस करती नजर आएंगी। यह हादसा एक स्टंट रिहर्सल के दौरान हुआ। 'कमांडो 2' और 'कमांडो 3' में अपने शानदार एक्शन के बाद, अदा इस नई फिल्म में एक्शन का स्तर और ऊंचा करने वाली हैं। चोट के बावजूद, अदा ने अपने जज्बे को बनाए रखा और कहा, दर्द अस्थायी है, लेकिन सिनेमा हमेशा चलता रहेगा। अब मैं एक एक्शन हीरोइन जैसी दिखती हूं।

अमरनाथ तीर्थयात्री बुधवार को बालटाल में वार्षिक अमरनाथ यात्रा के पहले चरण की शुरुआत से पहले बालटाल बेस कैंप पहुँचे।

भूमि पेडनेकर ने यूएनडीपी इंडिया के सतत विकास लक्ष्यों के प्रयासों की सराहना की

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को आगे बढ़ाने में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए यूएनडीपी इंडिया (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) के प्रयासों की सराहना की। भूमि ने इस पहल को सभी को एक साथ लेकर चलने और टिकाऊ भविष्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम करार दिया। भूमि यूएनडीपी इंडिया की एसडीजी की नेशनल एडवोकेट हैं। उन्होंने कहा, यह एक बड़ा और बदलाव लाने वाला मौका है। आज के युवा जागरूक हैं, जोश से भरे हुए हैं और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए समर्पित हैं। इस साझेदारी के जरिए हम ऐसा मंच बना रहे हैं, जहां युवा अपनी सोच और ऊर्जा से बड़े स्तर पर बदलाव ला सकें। यूएनडीपी इंडिया ने कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर एक साझेदारी की है। इसका मकसद जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता, गरीबी और सबका विकास जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर युवाओं को जागरूक और प्रेरित करना है।

यूएनडीपी इंडिया की प्रतिनिधि, डॉ. एंजेला लुसिगी ने इस साझेदारी के बारे में बात करते हुए कहा, यह साझेदारी युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, ताकि वह बदलाव लाने में सहायक बन सकें। भारत में युवा सिर्फ बदलाव की बात नहीं कर रहे, वह खुद बदलाव की अगुवाई कर रहे हैं। चाहे जलवायु की रक्षा की बात हो या फिर लैंगिक समानता की, युवा हर मोर्चे पर आगे हैं। अब कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क के साथ मिलकर हम इन कोशिशों को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि शहरों से लेकर गांवों तक युवा प्रेरित हो सकें।

यूएनडीपी इंडिया और कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क ने एक डिजिटल डॉक्यूमेंट्री सीरीज तैयार की थी, जिसे भारत की सबसे बड़ी स्टूडेंट कम्युनिटी में से एक 'अंडर 25' नाम की संस्था के साथ मिलकर बनाया गया था। इस डॉक्यूमेंट्री में युवाओं की प्रेरणादायक कहानियां दिखाई गईं कि कैसे वे बदलाव ला रहे हैं। यह सीरीज तीन हिस्सों में थी। इस वीडियो सीरीज में एक्ट्रेस और यूएनडीपी इंडिया की यूथ चैंपियन, संजना सांघी ने भी अपना समर्थन जताया था। साझेदारी का मकसद ओटीटी प्लेटफॉर्म, फिल्ममेकर, ब्रांड्स और फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों के साथ मिलकर ऐसे कैंपेन और इवेंट्स चलाना है, जो लोगों को सतत विकास लक्ष्यों के बारे में जागरूक करें।

पायल घोष ने बताया श्रीदेवी की कॉस्मेटिक सर्जरी का सच, शेफाली जरीवाला के निधन पर जताया दुख

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री शेफाली जरीवाला के दुखद निधन के बाद, एक्ट्रेस पायल घोष ने दिवंगत दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताया। श्रीदेवी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बात करते हुए पायल ने बताया कि श्रीदेवी अपनी बढ़ती उम्र को लेकर बहुत चिंतित रहती थीं। इसके लिए उन्होंने कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी। पायल ने कहा, ''साल 2017 की बात है जब मैं उनसे ओशिवारा में एक क्लिनिक पर मिली थी। हमारी बातचीत बस दो मिनट की थी। मैं हमेशा उनकी खूबसूरती और अंदाज की प्रशंसक रही हूं, इसलिए मैंने उनसे उनकी खूबसूरती का राज पूछा। मुझे हैरानी हुई जब उन्होंने कहा कि वह उम्र बढ़ने के डर से कॉस्मेटिक सर्जरी कराती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि वजन बनाए रखने और फिट दिखने के लिए वह खुद को भूखा रखती थीं।''

पायल घोष ने कहा, ''श्रीदेवी से उस बात के बाद उनका सोचने का तरीका बदल गया। उस बातचीत का मेरे जीवन पर बड़ा असर पड़ा। उसी वक्त मैंने अपने सभी स्किन ट्रीटमेंट्स को बंद करने का फैसला किया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी भी ऐसी हो।'' पायल ने बोटॉक्स और फिलर्स जैसे स्किन ट्रीटमेंट्स के इस्तेमाल की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये ट्रीटमेंट्स एक्टर्स की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा, ''पहले श्रीदेवी जी ने ये किया था और अब शेफाली जरीवाला की मौत एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाला उदाहरण है कि कैसे एक्टर्स बोटॉक्स, फिलर्स और इस तरह के ट्रीटमेंट्स के चलते अपनी जिंदगी जल्दी गवां रहे हैं। यह दुखद और अफसोसजनक भी है। ये ट्रीटमेंट्स एक्टर्स की जान ले रहे हैं। मुझे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
www.dakshinbharat.com
epaper.dakshinbharat.com
बेंगलूरु | गुरुवार | 03-07-2025 /dakshinbharat /dakshinbharat DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT HINDI DAILY
RNI No. 58061/93. Regn No.: NP/KA/BGS/2050/2018-2020 Posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026.

शहर के तेरापंथ सभा के तत्वावधान में तेरापंथ भवन में बुधवार को साध्वीश्री पावनप्रभाजी का चातुर्मास प्रवेश भव्य अहिंसा रैली के साथ हुआ। चातुर्मास के बाद प्रवेश कार्यक्रम मोयडू महल सभागार में रखा गया।

सम्मान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

बेंगलूरु एआईटी द्वारा नागरभावी खेल मैदान में बुधवार को यंत्र उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महेंद्र मुणोत ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। आयोजकों ने मुणोत का भी सम्मान किया ।

चातुर्मास निवेदन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

चेन्नई के केएलपी श्वेताम्बर स्थानकवासी संघ में विराजित राष्ट्रसंत कमलमुनिजी कमलेश से बेंगलूरु के वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ हनुमंतनगर के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर उनके दर्शन किए तथा वर्ष 2026 के चातुर्मास के लिए निवेदन किया। हनुमंतनगर संघ के मार्गदर्शक कल्याणसिंह बुरड़, अध्यक्ष गौतमचंद सिंघवी, उपाध्यक्ष हुक्मीचंद बाफना, उपाध्यक्ष मंत्री सुरेश धोका, नेमीचंद मांगीलाल बोहरा, सुनील बोहरा, महावीर बुबकिया आदि ने संतश्री से आशीर्वाद लिया।

कांग्रेस ने संरा सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता पाकिस्तान को मिलने पर मोदी सरकार की आलोचना की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु।कांग्रेस ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार पर पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण पदों पर काबिज होने से रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया और इसे भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका बताया। पाकिस्तान ने मंगलवार को कहा कि उसने जुलाई के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की अध्यक्षता संभाली है। विश्व निकाय के प्रमुख केंद्र सुरक्षा परिषद की यह अध्यक्षता, यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के तौर पर पाकिस्तान के दो साल के कार्यकाल का हिस्सा है। पाकिस्तान की यह अस्थायी सदस्यता जनवरी 2025 में शुरू हुई। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान, तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करेगा तथा संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद रोधी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यहां पत्रकारों से कहा, ''आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को अब वैश्विक सुरक्षा का ठेकेदार बना दिया गया है। अब शैतान ही कुर्सी पर बैठा है।'' उन्होंने कहा कि ''पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है जिसका आतंकवादियों को शरण देने, आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारत में आतंक फैलाने का सिद्ध इतिहास है'' और ''ऐसे में उसे वैश्विक नेतृत्व की भूमिकाएं दी जा रही हैं, जबकि भारत आज भी उसके प्रायोजित आतंकवादी हमलों का सामना कर रहा है।''

सुरजेवाला ने मोदी सरकार की ''चुप्पी और निष्क्रियता'' पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया, यह पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित पहलगाम आतंकी हमले के कुछ ही सप्ताह बाद हुआ है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा विदेश नीति पर सभी दिखावटी वादों के ''बावजूद'' पाकिस्तान को यह पद मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों नेता इस परिणाम को रोकने के लिए वैश्विक समर्थन जुटाने में विफल रहे।

सुरजेवाला ने कहा कि पाकिस्तान ने चार जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी समिति के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली, जबकि वह बार-बार आतंकवाद पर अंतरराष्ट्रीय प्रस्तावों का उल्लंघन करता रहा है। उन्होंने पूछा, ''प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं।'' कांग्रेस नेता ने सरकार की इस बात के लिए भी आलोचना की कि जब चीन के कथित समर्थन से पाकिस्तान ने इसी आतंकवाद-रोधी समिति में भारत विरोधी आतंकवादी अब्दुल रऊफ को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के भारत के प्रस्ताव को अवरुद्ध कर दिया था, तब सरकार ने कोई विरोध नहीं किया था।

'विद्याधन' पहल के तहत 'शिबूलाल परिवार' एक लाख जरूरतमंद विद्यार्थियों को देगा छात्रवृत्ति

बेंगलूरु। इंफोसिस के सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ एसडी शिबूलाल परिवार द्वारा स्थापित शिबूलाल फैमिली फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स (एसएफपीआई) पहल के तहत अपने प्रमुख विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम के माध्यम से आगामी चार वर्षों में सभी 28 राज्यों में आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों को 1लाख छात्रवृत्तियाँ प्रदान करेगा। यह कार्यक्रम ग्रेड 11 से स्नातक तक के विद्यार्थियों के लिए है जिसमें प्रति वर्ष 10 हजार से लेकर 75 हजार रुपए की छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। विद्याधन पहल के तहत आवासीय प्रशिक्षण, कैरियर मार्गदर्शन और रोजगार कौशल भी दिया जाता है। एसएफपीआई की संस्थापक और अध्यक्ष कुमारी शिबूलाल ने बताया कि हम मानते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ी समानता है, जिसमें व्यक्ति और राष्ट्र दोनों को स्थायी रूप से बदलने की शक्ति है। हमारा लक्ष्य विद्यार्थियों को सार्थक कैरियर की ओर मार्गदर्शन करने के लिए छात्रवृत्ति और मार्गदर्शन प्रदान करना है। हमारा लक्ष्य आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों को 1 लाख छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना है। विद्याधन आईटी प्लेटफ़ॉर्म की पारदर्शिता और 'ईच वन टीच वन' मॉडल के माध्यम से कार्य करता है। एसएफपीआई के सह-संस्थापक एसडी शिबूलाल ने बताया कि आज की तेजी से विकसित हो रही भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में, जहां शिक्षा ही ऊपर की ओर बढ़ने का एकमात्र साधन है, कम सुविधा प्राप्त पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए वित्तीय पहुंच महत्वपूर्ण है।

तेरापंथ भवन में हुआ चातुर्मास प्रवेश

आत्मा पर लगे दाग, वैमनस्य आदि मिटाने का समय है चातुर्मास : साध्वीश्री पावनप्रभा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

केजीएफ। शहर के तेरापंथ सभा के तत्वावधान में तेरापंथ भवन में बुधवार को साध्वीश्री पावनप्रभाजी का चातुर्मास प्रवेश भव्य अहिंसा रैली के साथ हुआ। चातुर्मास के बाद प्रवेश कार्यक्रम मोयडू महल सभागार में रखा गया। महिला मंडल की नई अध्यक्ष सरिता बांठिया ने मंगल स्तुति की। सभा के अध्यक्ष सुदर्शन बांठिया ने सभी का स्वागत किया। दक्षिण कर्नाटक के आंचलिक संयोजक प्रकाश लोढ़ा ने साध्वीश्री का स्वागत किया। महिला मंडल की मंत्री चेतना बांठिया ने शुभकामनाएं दी। इस मौके पर ज्ञानशाला के संस्थापक कमलेश हिंगड, तेरापंथ संघ के वरिष्ठ सदस्य मूलचन्द नाहर, महासभा कार्यसमिति के सदस्य संजय बांठिया सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे।

प्रवेश के मौके पर साध्वीश्री पावनप्रभाजी कहा कि साधु-साध्वियों का आगमन पुण्योदय से होता है। संत ज्ञान, दर्शन, चारित्र व तप का प्रकाश लेकर आते है। जिस तरह बाजा बजने से पैर थिरकते हैं, वैसे ही चातुर्मास के दौरान यदि श्रावक श्राविकाएं सक्रिय रहेंगे तो संत उनसे ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं । जिस तरह रिमूवर के माध्यम से दाग मिटाए जाता है उसी प्रकार आत्मा पर लगे दाग, वैमनस्य आदि मिटाने का समय होता है चातुर्मास। साध्वीश्री आत्मयशाजी, उन्नतयशाजी,रम्यप्रभाजी ने पावन प्रभा सुपर मार्केट' नामक चातुर्मास कार्यकाल में होने वाले कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। सभा के मंत्री सुशील बांठिया ने धन्यवाद दिया तथा संचालन प्रिया बांठिया ने किया। इस प्रवेश के मौके पर मालूर, गुड़ियात्तम, हिरीयूर, वेल्लूर, बेंगलूरु, कोलार, मूलबागल, बंगारपेट, होसपेट आदि शहरों के श्रावक श्राविकाओं की अच्छी उपस्थिति थी।

गुरु ज्येष्ठ पुष्कर जैन आराधना केन्द्र का उदघाटन 6 को

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर के गुरु ज्येष्ठ पुष्कर जैन चेरिटेबल ट्रस्ट व आराधना केन्द्र के तत्वावधान में उपप्रवर्तकश्री नरेशमुनिजी, शालिभद्रमुनिजी व साध्वीश्री दर्शनप्रभाजी की प्रेरणा से इटा अपार्टमेन्ट के पास केपी अग्रहारा में नवनिर्मित गुरु ज्येष्ठ पुष्कर जैन आराधना केन्द्र के उद्घाटन के मौके पर त्रिदिवसीय महोत्सव का शुभारंभ 4 जुलाई से प्रारंभ होगा। शुक्रवार को सुबह 7 बजे भरत चक्रवर्ती भोजन मंडप का उदघाटन, तत्पश्चात गुरु ज्येष्ठ पुष्कर नगरी का उद्घाटन और आधार स्तंभ लाभार्थी परिवार का सम्मान किया जाएगा।

शनिवार को सुबह को ट्रस्टी परिवारों का सम्मान, दोपहर में मेहंदी एवं धार्मिक नाटिका होगी। रविवार को सुबह 9 बजे गुरु ज्येष्ठ पुष्कर जैन आराधना केन्द्र का उदघाटन होगा, साथ ही अतिथि कक्ष लाभार्थी एवं अन्य लाभार्थी परिवारों का सम्मान किया जाएगा। उद्घाटन के मौके फलेचुंदड़ी का आयोजन भी किया गया है। शाम को भक्ति संध्या में गायक वैभव बागमार प्रस्तुति देंगे। सोमवार को सुबह उपप्रवर्तकश्री नरेशमुनिजी, शालिभद्रमुनिजी का चातुर्मास प्रवेश, ध्वजारोहण व संतों का प्रवचन होगा।

आयोजकों ने बताया कि महोत्सव के चारों दिन तीनों समय की नवकारशी एवं भक्ति का आयोजन किया गया है। भवन के मुख्य लाभार्थी अशोककुमार-महेन्द्रकुमार रांका परिवार, भूमिपूजन व शिलान्यास के लाभार्थी घेवरचन्द मीठालाल दीपचन्द भंसाली परिवार, भवन उद्घाटन लाभार्थी पारसमल शांतिलाल सुरेन्द्रकुमार सालेचा परिवार, मुख्य प्रवचन हॉल के लाभार्थी उत्तमचन्द प्रकाशचन्द पदमराज रातड़िया परिवार, रांका रिसेप्शन हॉल के लाभार्थी बाबूलाल रांका व अशोककुमार महेन्द्रकुमार रांका परिवार, श्रमण श्रमणी पुष्प जवाहर ब्लॉक के लाभार्थी दिलीपकुमार वंसतकुमार गणधर चौपड़ा परिवार, वृहत बहुउपयोगी डॉयनिंग हॉल के लाभार्थी वगतावरमल माणकचन्द पारेख परिवार तथा फलेचुन्दड़ी के लाभार्थी पंचकेसरी बड़ेरा परिवार वाले हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष नेमीचन्द सालेचा व महामंत्री महावीरचन्द मेहता ने सभी गुरु भक्तों को कार्यक्रम में शामिल होने का निवेदन किया।

बीजेएस मैसूरु ने सीए व डॉक्टर्स का किया सम्मान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मैसूरु। भारतीय जैन संगठन (बीजेएस), मैसूर चैप्टर द्वारा सीए-डे (चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस) और डॉक्टर्स डे के अवसर पर एक कार्यक्रम में समाज के प्रति समर्पित और उत्कृष्ट सेवा देने वाले चिकित्सकों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सम्मान कर उनके योगदान को सराहा गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से डॉ. मदन लाल, विजयराज रांका, सीए उम्मेद राज रांका और सीए सुनील लुणावत का सम्मान कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। चैप्टर के अध्यक्ष राजन बागमार ने कहा कि डॉक्टर्स और सीए जैसी प्रोफेशनल सेवाएं समाज के आधार स्तंभ हैं, और इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इस मौके पर संस्था के कोषाध्यक्ष मनोहर सांखला, उपाध्यक्ष अमित चौहान, कुशल परलेचा, नेमीचंद बडोला सचिव राजेन्द्र देसरला, नवरतन पिटिया, सुनील पटवा आदि उपस्थित थे। बीजेएस कर्नाटक राज्य के सचिव प्रकाश गुलेच्छा ने मैसूर चैप्टर के प्रयासों की सराहना की ।

कर्नाटक की जैन परंपरा का इतिहास गौरवशाली है : आचार्यश्री विमलसागरसूरी

लक्कुंडी(गदग)/दक्षिण भारत। गदग वर्षावास के लिए जाते समय बुधवार को एक दिन के प्रवास पर आचार्य विमलसागरसूरीश्वरजी अपने शिष्य गणि पद्मविमलसागरजी और मुनिजनों के साथ लक्कुंडी पहुंचे। उन्होंने सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उनके साथ पदयात्रा की। इस मौके पर कोप्पल नगरपालिका के अध्यक्ष अमज़द पटेल ने भी लक्कुंडी पहुंचकर जैनाचार्य से आशीर्वाद ग्रहण किए। इस मौके पर आचार्य विमलसागरसूरीश्वरजी ने कहा कि अपनी सांस्कृतिक चेतना को जगाने और विरल परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने गौरवशाली इतिहास को जानना अत्यंत जरूरी है। जो अपने अतीत के इतिहास को नहीं जानते, वे अपने भविष्य को सुरक्षित रखने में भी सफल नहीं होते। सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि कर्नाटक में जैन परंपरा का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। यहां के प्रारंभिक चार महाकवि पंपा, पोन्ना, रन्ना और जन्ना धर्म मान्यता से जैन थे। उनकी साहित्यिक रचनाएं कन्नड़ भाषा का गौरव हैं। पश्चिम भारत के चालुक्य वंश के अंतर्गत सामन्त राजा की रानी अतिमब्बे भी कर्नाटक के जैन इतिहास का एक उल्लेखनीय व्यक्तित्व है, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता।

आचार्य विमलसागरसूरीश्वरजी ने विस्तार से बताया कि लक्कुंडी और उसके आसपास की भूमि अतिमब्बे के पवित्र कार्यों की याद दिलाती है। न्याय-नीतिपूर्वक का शासकीय कार्य, समाज के हर वर्ग की सेवा, साहित्यिक अवदान, धर्मशास्त्रों का प्रसार-प्रचार, स्वाध्याय और जैन मंदिरों के निर्माण करवाकर अतिमब्बे ने अपने जन्म को सफल कर दिया था। उन्होंने पंचधातु की हजारों तीर्थंकर प्रतिमाएं बनाकर भक्तों के घर-घर तक पहुंचाई थी। कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने रानी अतिमब्बे पर उपन्यास, काव्य और जीवन चरित्र लिखे हैं। गुरुवार को प्रातः आचार्य विमलसागरसूरीश्वरजी अपने मुनिमंडल के साथ गदग शहर की सीमा में पधारेंगे। जैन संघ के अध्यक्ष पंकज बाफना के निवास पर वर्षावास की निमंत्रण पत्रिका का आलेखन किया जाएगा।

शौचालय के अंदर महिला सहकर्मी का वीडियो बनाने के आरोप में इंफोसिस का कर्मचारी गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। बेंगलूरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलाके में स्थित इंफोफिस कंपनी के परिसर के अंदर शौचालय में महिला सहकर्मी की वीडियो बनाने के आरोप में बुधवार 30 वर्षीय कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। कंपनी के मानव संसाधन (एचआर) विभाग के कर्मचारियों ने आरोपी स्वप्निल नागेश माली को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र के सांगली का रहने वाला माली कंपनी में 'सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट' है। घटना पर इंफोसिस की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई।

पुलिस के अनुसार, घटना सोमवार सुबह की है जब महिला ने शौचालय के बगल में परछाई और हलचल देखी। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि कुछ ही क्षण बाद उसने देखा कि माली शौचालय के बगल में खड़ा होकर मोबाइल फोन से वीडियो बना रहा था। इस बाद महिला चिल्लाते हुए बाहर भागी और अपने सहकर्मियों को इसकी जानकारी दी।

इस बीच, भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को एचआर कर्मचारियों ने पकड़ लिया। आरोपी के फोन की जांच करने पर एचआर कर्मियों को पीड़िता का एक वीडियो और एक अन्य महिला कर्मचारी का गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया वीडियो मिला। आरोपी ने कई बार माफी मांगी और 'वीडियो डिलीट' कर दिए, लेकिन एचआर कर्मचारियों ने 'डिलीट' होने से पहले सबूत के तौर पर वीडियो की तस्वीर ले ली। महिला ने बाद में इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

निलंबित आईपीएस अधिकारी को बहाल करने के आदेश को चुनौती

बेंगलूरु। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के उस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जिसमें अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विकास कुमार विकास को बहाल करने का आदेश दिया गया था।

विकास को पिछले महीने यहां चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की घटना के बाद निलंबित किया गया था। इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 56 अन्य लोग घायल हो गए।

कैट ने मंगलवार को विकास के निलंबन को रद्द कर दिया और कहा कि राज्य की कार्रवाई का कोई ठोस आधार नहीं है।

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company, 6/4 , Ist floor, Cantonment station road, Bengaluru-51 and printed at Dinasudar Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. **Editor-Shreekant Parashar**,
(*Responsible for selection of news under PRB Act.) Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.
HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com